राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 211 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,22 जनवरी 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

बीड़ी लाने में हुई देर पर गुस्साए पिता ने बेटे को जिंदा जलाया

हैदराबाद। दुकान से बीड़ी लाने में हुई देर से गुस्साए पिता ने अपने 10 साल के बेटे को कथित रूप से जिंदा जला दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बच्चे को 17 जनवरी की रात को जिंदा जलाया गया। आरोपी पिता बच्चे की पढ़ाई को लेकर भी नाराज था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 90 प्रतिशत जली अवस्था में बच्चे को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां बुधवार की रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शराबी पिता ने अपने घर में कथित रूप से बच्चे पर तारपीन का तेल डाला और माचिस से अपनी बीड़ी जलाने के बाद उसी तीली से बच्चे को आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में हेस्टिंग्स जूट मिल में आग लगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 145 साल पुरानी हेस्टिंग्स जूट मिल में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग से गोदाम में कच्चे जूट के भंडार को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है, हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने बताया कि तीन दमकल वाहनों को आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया और स्थिति अब नियंत्रण में है। हेस्टिंग्स जूट मिल के एक अधिकारी ने कहा कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ और मिल का कार्य संचालन सामान्य है। यह मिल 1875 में शुरू हुई थी।

उच्चतम न्यायालय ने मादक पदार्थ रैकेट मामले में कन्नड़ अभिनेत्री को जमानत दी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मादक पदार्थ रैकेट मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफकी पीठ ने मामले में अभिनेत्री एवं अन्य को जमानत नहीं देने से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय के पिछले साल तीन नवंबर के फैसले को रद्द कर दिया। मादक पदार्थों पर रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत इन सभी के खिलाफमामला दर्ज किया गया था। कर्नाटक पुलिस ने मामले में पिछले साल सितंबर में द्विवेदी एवं अन्य को गिरफ्तार किया था।

भारत फ्रांस वायुसेना का सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट शुरु

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में भारतीय और फ्रांस वायुसेना का अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट-21 शुरु हो गया। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार सुबह डेजर्ट नाइट -21 में शामिल होने चार के लिये फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान फ्यूअल टैंकर ए-320 की मदद से फ्रांस से उड़ान भरकर सीधे जोधपुर पहुंचे। उनके साथ दो एटलट ए 400 एम परिवहन विमान और ए330 बहुउद्देश्यीय टैंकर परिवहन विमान आये हैं, जबकि भारत की ओर से फ्रांस से ही प्राप्त राफेल के साथ ही मिराज 2000, एसयू-30 एम के आई, आईएल 78 ईंधन विमान के अलावा अवाक्स और अन्य आधुनिक वैमानिकी युद्धक प्रणाली शामिल की गयी है। सूत्रों ने बताया कि एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट -21 20 से 24 जनवरी तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच जुड़ाव की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-फ्रांसीसी रक्षा सहयोग के तहत अब तक भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना के बीच कई सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने 2018 में आगरा और ग्वालियर में वायुसेना स्टेशनों पर फ्रांसीसी वायुसेना की मेजबानी की थी।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला को दी बधाई

नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के शपथ लेने के बाद दोनों को और अमेरिका के लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को उनके लोकतंत्र के एक नए अध्याय पर बधाई। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को शुभकामनाएं! उद्घाटन दिवस। उनकी यह टिप्पणी बाइडेन द्वारा अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद आई।

किसान आंदोलन: नहीं निकला कोई समाधान, आज फिर से होगी वार्ता

ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसान

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो गई है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से मना किया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि, %दिल्ली पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर अनुमति देना मुश्किल है और सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने कह दिया है कि हम रिंग रोड पर ही रैली करेंगे। फिर उन्होंने (पुलिस) कहा कि ठीक है हम देखते हैं। कल हमारी पुलिस के साथ फिर बैठक होगी।

बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में लगे हुए हैं। हजारों ट्रैक्टर अलग-अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। वहीं दिल्ली पुलिस किसानों को ट्रैक्टर मार्च न निकालने पर मनाने में जुटी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच गुरुवार को दिल्ली के मंत्रम रिसॉर्ट में अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड आर्डर संजय सिंह, स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक, जॉइंट सीपी एसएस यादव और दिल्ली पुलिस के दो एडिशनल डीसीपी के अलावा यूपी और हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में जान गंवाने वाले चार किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद दी

नए कृषि कानूनों के खिलाफचल रहे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लुधियाना के चार किसानों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भीषण ठंड के बावजूद पिछले करीब दो महीनों से तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफहजारों किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। प्रदर्शन में भाग लेने वाले कई किसानों की मौत दिल के दौरे पड़ने और सड़क दुर्घटनाओं सहित विभिन्न कारणों से हुई है। लुधियाना के उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के निर्देश पर उन किसानों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है, जो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफप्रदर्शन के दौरान दुर्भाग्य से अपनी जान गंवा चुके हैं।

सीधे-सीधे रद्द करे कानून...

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों एवं सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार रहने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसे 'रोज नए जुमले' बंद कर 'कृषि विरोधी कानूनों' को रद्द करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, '' रोज़ नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे-सीधे कृषि-विरोधी क़ानून रद्द करो!'' उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कारपोरेट घरानों की 'कृपा' पर रहना पड़ेगा।

मोदी को किसान भेज रहे अपनी 'मन की बात', पोस्टकार्ड के जरिए गिना रहे अपनी परेशानी

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। की बात लिखकर भेज रहे हैं। किसान पोस्टकार्ड के जरिए अपनी बात पीएम तक पहुंचाकर तीनों कानूनों को जल्द रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के 'मन की बात' पीएम मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम, जिसमें अक्सर पीएम अपने मन की बात देश के लोगों से कहते हैं, की ही तर्ज पर किसानों के मन की बात की पहल की गई है। लोगों से कहा गया है कि वे कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी को अपने मन की बात बताएं। पोस्ट कार्ड के जरिए ये बात पहुंचाई जा रही है। बता दें कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों के आगे कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है तो वहीं कानूनों को निरस्त करने की मांग भी खत्म होती नहीं दिख रही है। एक ओर किसान यूनियन की ओर से किसान नेता सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं वहीं किसान आंदोलन के समर्थक पीएम मोदी तक किसानों की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैंपेन को चलाने वालों में से एक कंवरदीप कौर ने बताया कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों तक पहुंचते हैं। हमने सोचा कि किसानों के मन की बात पीएम मोदी तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा,'अब पीएम मोदी को किसानों की मन की बात सुननी चाहिए। हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। भारत एक लोकतंत्र है और पीएम मोदी तक किसानों की बात पहुंचाना जरूरी है।'

मौत बना वैक्सीन सेंटर

भीषण हादसे में 5 की गई जान, सीरम इंस्टीट्यूट में चीख-पुकार

मुंबई। गुरुवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में भीषण हादसा हो गया। इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। इस हादसे में इंस्टीट्यूट के पांच कर्मचारियों की मौत हो गई। इस बारे में पुणे के मेयर ने पुष्टि की है। बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशिल्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाडियाँ वहाँ तत्काल पहुंच चुकी थी। बताया जा रहा कि आग नए प्लांट में लगी, जहां पर अभी वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस घटना के बाद बिल्कुल चौकन्नी हो गई है। वहीं सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

सीरम इंस्टीट्यूट में हुए इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मिली जानकारी के अनुसार, आग नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन की यूनिट में आग नहीं लगी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बात की है। आग लगभग नियंत्रण में है। लेकिन भयानक होने की वजह से अभी धुआं है। इस हादसे में 6 लोगों को बचाया गया है।

हादसे के बारे में सीएम ठाकरे ने कहा कि इमारत में बीसीजी वैक्सीन बनती थी और इसका कोविशील्ड वैक्सीन से लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच होगी।

- पुणे के सिरम इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग
- गुरुवार दोपहर के 2:30 बजे के आसपास लगने की खबर
- सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (सीआईआई) के मंजारी प्लांट के एक निमाणाधीन भवन में गुरुवार दोपहर को भीषण आग लगी. दोपहर 2 बजे, मंजारी के सीआईआई परिसर में धुएं के घने बादल निर्माणाधीन इमारत से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते थे...

वैक्सीनेशन प्लांट सुरक्षित

साथ ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। देश और दुनिया भर में इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन प्लांट सुरक्षित है।

इसके अलावा हादसे के बारे में चीफ फायर ऑफिसर ने कहा कि दमकल विभाग को 2.30 बजे आग की सूचना मिली। हम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुटे हैं। पहले हमने 9 लोगों की बचाया। ऐसे में स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद हमें इमारत की पांचवीं मंजिल पर 5 शव मिले।

फिलहाल इस हादसे पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि हमें अभी कुछ परेशान करने वाले अपडेट मिले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से घटना में कुछ लोगों की जान गई है। इससे हमें गहरा दुख हुआ है और मृतकों के परिवार के सदस्यों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.1 करोड मकानों के निर्माण को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 1.1 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई जिनमें से 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और 41 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी कर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 52 वीं बैठक में 168,606 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। यह बैठक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मिश्र ने बताया कि कई राज्यों ने पर्यावरण से जुड़े कारणों की वजह से भूमि के आकार में होने वाले बदलाव , अंतर शहरी विस्थापन और अलग-अलग तरह के लाभार्थियों के लिए तय की गई प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि कारणों से प्रस्तावित योजना की पुनर्समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। योजना के तहत 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और 41 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं।

मोदी सरकार 15 अगस्त 2022 तक सभी को घर मुहैया कराएगी: शाह

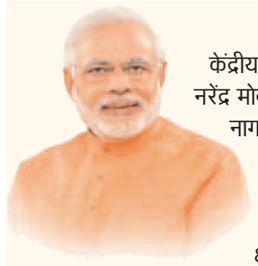

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार 15 अगस्त, 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया कराएगी। शाह ने अहमदाबाद के शिलज में एक किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान यह बात कही। शाह ने कहा, जिस तरह से हमारी भाजपा सरकार देश में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 करोड़ से अधिक किफायती आवास प्रदान किए हैं।

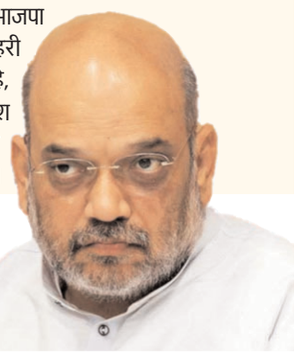

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज, उठेंगे चौट लीक व किसानों के मुद्दे

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। कांग्रेस ने अपनी कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक 22 जनवरी को बुलाई है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी इस बैठक में किसानों के मुद्दों, अर्नब गोस्वामी चौट लीक और कोविड-19 महामारी पर चर्चा करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि यह बैठक वर्चुअल आयोजित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। हजारों किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई है।

अध्यक्ष के चुनाव पर होगी चर्चा

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी कार्यसमिति की बैठक शुक्रवार को सुबह होगी। इस डिजिटल बैठक में हिस्सा लेने के लिए कार्यसमिति के सभी सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक बार फिर गहमागहमी तेज हो गई है।

खराब प्रदर्शन के बाद असंतुष्ट खेमा सक्रिय

बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और उसके बाद से पार्टी में फिर स्थायी अध्यक्ष की मांग तेज हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने हाल में एक बार फिर भाजपा की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए स्थायी अध्यक्ष की मांग उठाई है।

आपत्तिजनक नारे पर कार्रवाई: हुगली में 3 बीजेपी नेता गिरफ्तार

गोली मारो... के नारे

हुगली। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में बीजेपी युवा मोर्चा के तीन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल पुलिस ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश शॉ और दो पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दोनों को चंदननगर कोर्ट में पेश किया गया है।

दरअसल बुधवार को हुगली के चंदननगर में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की रैली थी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के गद्दारों को, गोली मारो... के नारे लगाए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले में एफआईआर दर्ज करके तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।

बंगाल पुलिस ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश शॉ और दो पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, कोर्ट में हुई पेशी

बुधवार को हुगली के चंदननगर में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की रैली थी, इस दौरान लगे थे गोली मारे.. केनारे

पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेश शॉ, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता को नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हुगली में बुधवार को सुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में रैली निकाली गई थी। इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रैली में गोली मारो... के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। बता दें कि इस नारे को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी काफी बवाल उठाया। तब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ऐसे ही नारे लगाए थे जिसे लेकर विवाद हुआ था।

सीआरपीएफ 'कोबरा' कमांडो बटालियन में महिलाकर्मियों को शामिल करने पर मिली सहमति

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जंगल युद्ध में महारत रखने वाले अपने 'कोबरा' कमांडो बल में महिला कर्मियों को शामिल करने पर विचार कर रहा है। सीआरपीएफ प्रमुख ए पी माहेश्वरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। खुफिया सूचना आधारित जंगल युद्ध अभियानों के लिए सीआरपीएफके तहत 2009 में 'कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन' (कोबरा) की 10 इकाइयां गठित की गई थी। माहेश्वरी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हम कोबरा में महिलाओं को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।'' ज्यादातर कोबरा टीमें नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात हैं और कुछ टीमें उग्रवाद रोधी अभियानों के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में रखी गई हैं। कोबरा इकाइयों में शामिल किये जाने वाले सैनिकों को मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर कड़े मानदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। सीआरपीएफमें 1986 से ही महिला कर्मी हैं, जब इसकी प्रथम महिला बटालियन का गठन किया गया था। बल में अभी ऐसी छह इकाइयां हैं। बल में करीब 3.25 लाख कर्मी हैं और यह देश का सबसे बड़ा अर्द्धसैनिक बल है। इसका गठन आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था।

इमरान के गले की हड्डी बना फॉरेन फंडिंग केस, विपक्ष का आरोप- यह पाक की राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों को फॉरेन फंडिंग केस बड़े हथियार के रूप में मिल गया है। विपक्षी दलों के संगठन पीडीएम ने अब इस मामले में इमरान खान की घेराबंदी तेज कर दी है। पीडीएम के प्रमुख फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है।

पीडीएम प्रमुख रहमान ने कहा कि इमरान खान ने विदेशों से मिले करोड़ों रुपयों के फंड का इस्तेमाल देश में राजनीतिक

अराजकता और चुनाव में धांधली के लिए किया है। इस मामले की सुनवाई चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है और सत्ता के दबाव में इसको छह साल से लगातार लंबित किया जा रहा है।

2014 में दर्ज किया गया था फॉरेन फंडिंग केस

सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 में दर्ज किया गया था। अब इस मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। इस मामले के निर्णय में देरी किए जाने पर पाकिस्तान के ग्यारह विपक्षी दल चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे है।

इधर सीनेट (उच्च सदन) के उपाध्यक्ष सलीम मांडवीवाला ने नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस सरकारी एजेंसी के माध्यम से नेताओं पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्षी नेता मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनएबी भी चुन-चुन कर इमरान खान के विरोधियों का उत्पीड़न कर रही है। यह एजेंसी इमरान खान की पार्टी पीटीआइ की सहयाक संस्था के रूप में काम कर रही है।

हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में भूखों रहने को मजबूर हैं एक करोड़ बच्चे, बिना गर्म कपड़ों के काट रहे ठंड

काबुल। युद्ध और हिंसा के साए में अफगानिस्तान के बच्चों के सामने इन दिनों भूख एक बड़े संकट की तरह मुंह बाये खड़ा है। लंबे समय से हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में एक करोड़ से अधिक बच्चे बहुत ही खराब स्थिति में हैं। इन बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं तो बाद की बात है खाने की समस्या का तुरंत समाधान आवश्यक है। यह समस्या 2021 में भी बने रहने की आशंका है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अरबों डालर मदद की जरूरत पड़ेगी। यह आकलन अफगानिस्तान में काम

करने वाले एक मानवाधिकार संगठन 'सेव द चिल्ड्रन' का है।

संगठन के कंट्री डायरेक्टर क्रिस न्यामांडी के अनुसार युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में एक करोड़ अस्सी लाख अफगान नागरिकों को खाने की समस्या है। इनमें से नब्बे लाख से ज्यादा बच्चे हैं। संगठन का मानना है कि 2021 में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में ही लगभग तीन सौ करोड़ डालर की मदद की जरूरत होगी। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में बच्चों की हालत पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

लंदन की संगठन के रिपोर्ट में एक 10 वर्षीय बच्ची ब्रिश्ना का जिक्र है जो पूर्वी नांगरहार प्रांत की रहने वाली है। उसने बताया कि उनका परिवार हिंसा के कारण अपना घर छोड़ दूसरे जिले में रहने को मजबूर है। उसने बताया,'जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है क्योंकि एकमात्र मेरे पिताजी कमाने वाले हैं और अभी बीमार हैं।' ब्रिश्ना ने बताया कि सही तरीके से खाना खाए लंबा समय बीत गया। कोरोना महामारी ने बच्चों की स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया है। यहां के लोगों का मानना है कि सरकार के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की खराब हालत ने भी इन दिक्कतों को और बढ़ाया है। सेव द चिल्ड्रन की दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार तीन लाख बच्चे सर्दीके मौसम में आवश्यक गर्म कपड़ों से भी वंचित हैं और इसलिए बीमार हो रहे हैं। आर्गेनाइजेशन की ओर से अफगानिस्तान के 34 में से 12 प्रांतों के 1 लाख परिवारों को जाड़े में राहत के लिए मदद दी गई। इसके तहत इन्हें ईंधन और हीटर, कंबल, गर्म कपड़े जैसे कोट, मोजे, जूते और टोपी दी गई है।

बर्फ ने रोकी रफ्तार: जापान में बर्फीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी जीरो हुई, नेशनल हाईवे पर 134 वाहन टकराए

टोक्यो। जापान के तोहोकू एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को 134 वाहन आपस में टकरा गए। बर्फबारी के कारण यहां विजिबिलिटी जीरो हो गई थी। ड्राइवर कुछ दूर तक भी नहीं देख पा रहे थे। इस वजह से वाहन आपस में भिड़ गए। इन हादसों में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं।

सरकार ने बयान जारी कर बताया है कि ये हादसे मियागी के उत्तरी इलाके में हुए। इससे करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क पर वाहन फंस गए। हालांकि, बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गाड़ियां चलाने पर रोक लगाई थी। बर्फीले तूफान की वजह से इसका भी फायदा नहीं हुआ।

डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि 200 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 12 को अस्पताल भेजना पड़ा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

जापान में इस बार भारी बर्फबारी

जापान के कुछ हिस्सों में असामान्य तरीके से भारी बर्फबारी हो रही है। यहां एक महीने में तीन बर्फीले तूफान आ चुके हैं। पिछले सप्ताह आए तूफान की वजह से कई इलाकों में 7 फीट तक बर्फ जम गई थी। कई घर और गाड़ियां बर्फ में दब गईं। 1200 से ज्यादा ट्रक होन्शिकू नेशनल हाईवे पर फंसे रहे थे।

हालात बिगड़े तो इन वाहनों में फंसे लोगों के लिए अधिकारियों ने कंबल और खाना पहुंचाया। इस दौरान तीन दिन में फुजिवारा शहर में दो मीटर से ज्यादा बर्फ गिरी है। यह इतिहास की सबसे ज्यादा बर्फबारी मानी जा रही है।

कैपिटल हिल हिंसा पर राजनीति: अमेरिकी सांसद कोरोना और मौतों को भूल दंगे और ट्रम्प की चर्चा में जुटे

वॉशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और पोस्ट के विषयों में चुनिंदा शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 15 दिन से रोज 2 लाख नए मरीज और रोज औसतन 1,500 से ज्यादा मौतों के बावजूद सांसद इससे बेफिक्र हैं। वे इस पर ज्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी चर्चा में कोविड या कोरोनावायरस का जिक्र मार्च 2020 के बाद दूसरे सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जबकि चुनाव के वक्त उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा इसी को लेकर की थी। इसके बजाय वे ट्रम्प, आतंकी, दंगे, लोकतंत्र, विद्रोह, विरोध प्रदर्शन, पुलिस की नाकामी और कानून और व्यवस्था का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं।

हिंसा से पहले कोरोना बड़ा मुद्दा, अब राजनीति बड़ी

6 जनवरी से पहले अमेरिकी सांसद सबसे ज्यादा चर्चा कोरोना और उससे हो रही मौतों को लेकर कर रहे थे, लेकिन 6 जनवरी के बाद से उनका पूरा ध्यान राजनीति पर है। जबकि कोरोना के मरीज और मौतें बढ़ रही हैं। दोनों ही पार्टियों के सांसद अब कोरोना की न तो फिक्र कर रहे हैं और न ही ज्यादा जिक्र। अब सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा में से कोरोना धीरे-धीरे कम या गायब हो रहा।

रिपब्लिकन पर गुस्से के इमोजी 5 दिन में 17फीसदी बढ़े

सांसदों की पोस्ट और उन पर यूजर्स की प्रतिक्रिया के विश्लेषण से पता चला है कि रिपब्लिकन सांसदों की पोस्ट पर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। 6 जनवरी के बाद 5 दिन में उनकी पोस्ट पर गुस्से के इमोजी 17फीसदी बढ़ गए। रिपब्लिकन की पोस्ट के रीट्वीट 56त्न तक घट गए हैं, जबकि फेवरिट बताने वाले 60त्न तक घटे हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक सांसदों के रीट्वीट दोगुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। उनका यूजर एंगेजमेंट तेजी से बढ़ रहा है।

ट्रम्प समर्थक कानून और व्यवस्था की बातें कर रहे

प्यू रिसर्च के मुताबिक सांसद अपनी पोस्ट में लोकतंत्र, दंगे, हिंसा, टेररिज्म, अटैक शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं।

कैपिटल हिल में 7 जनवरी को हिंसा हुई थी

अमेरिका में 7 जनवरी को हथियारबंद ट्रम्प समर्थक संसद में घुस गए थे और जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की गई थी। वे चाहते थे कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को रद्द किया जाए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पांच लोगों की मौत हो गई थी।

सैमसंग के वाइस चेयरमैन गिरफ्तार: ली जे-योंग को ढाई साल की जेल, पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी को 200 करोड़ की रिश्वत देने का था आरोप

टोक्यो। सोमवार को सैमसंग के वाइस चेयरमैन ली जे-योंग को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने ढाई साल की सजा सुनाई है। योंग पर कारोबारी लाभ के लिए पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन-हे के सहयोगी को रिश्वत देने का आरोप था। इस मामले में सैमसंग के पूर्व अध्यक्ष पार्क जियुन हे भी शामिल हैं। कोर्ट ने दोनों को ही जेल भेजने का आदेश दिया है। पिता की मौत के बाद योंग ने 2014 में कंपनी की कमान संभाली थी। सियोल हाईकोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो ली कोर्ट में मौजूद थे। उन्हें कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि योंग काफी समय से जेल से बाहर थे क्योंकि उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी। 52 वर्षीय ली पर सबसे पहले फरवरी 2017 में आरोप दायर किए गए थे। उन पर 27.4 मिलियन डॉलर (लगभग 200 करोड़ रुपए) की रिश्?वत देने का आरोप था। वर्ष 2017 में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ऊपरी अदालत में अपील के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।

क्या था मामला?

योंग पर आरोप था कि उन्होंने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कई बड़े लोगों को रिश्वत दी। इसमें साउथ कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन-हे का नाम भी सामने आया था। उन्हें महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ली ने सक्रिय रूप से रिश्वत दी और राष्ट्रपति से अपने कारोबार को चलाने में मदद करने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने को कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि- यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की टॉप कंपनी और ग्लोबल इनोवेटर सैमसंग, जब भी राजनीतिक शक्ति में बदलाव होता है, बार-बार अपराधों में शामिल होती है।

पाकिस्तान में मंदिर को नुकसान पहुंचाने पर बढ़ाई गई सुरक्षा, नियमों में किया गया बदलाव

पेशावर। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का मामला पिछले दिनों सुर्खियों में आने के बाद यहां मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खैबर पख्तनूख्वा प्रांत के एबटाबाद स्थित एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कट्टरपंथी कोशिश कर रहे थे। मंदिर तोड़े जाने की आशंका अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने की थी। शिकायत के बाद मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस मंदिर की जमीन पर माफियाओं की भी नजर थी। अधिकारियों के अनुसार अब इस जमीन की लीज न तो परिवर्तित होगी और न ही इस बेचा जा सकेगा। भविष्य में इसका कामर्शियल उपयोग करने पर भी रोक लगा दी गई है।

दिसंबर महीने में खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेरी गांव में बने एक मंदिर पर कट्टरपंथी उपद्रवियों के साढ़े तीन सौ से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। इन लोगों ने मंदिर को हानि पहुंचाने के साथ ही परिसर में बनी संत की समाधि का भी अपमान किया था। मंदिर को विस्तार देने की योजना पर कार्य चल रहा था, तब इलाके के कट्टरपंथी मुस्लिम भड़क गए और उन्होंने एकत्रित होकर मंदिर पर हमला कर दिया।टेरी गांव में तो ज्यादा संख्या में हिंदू नहीं रहते हैं लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले हिंदू बड़ी संख्या में इस प्राचीन

मंदिर में दर्शन को आते थे। साल 1997 में भी इस मंदिर पर कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया था और उसे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। उसके बाद एक और मंदिर पर हमले का प्रयास किया गया था।

थाइलैंड में राजतंत्र का अपमान करने पर महिला को सुनाई गई 43 साल की सजा

बैंकाक। थाइलैंड में एक पूर्व सिविल सर्वेंट को राजतंत्र का अपमान करने के आरोप में रिकॉर्ड 43 साल की सजा सुनाई गई है। 65 साल की इस महिला ने 29 बार राजतंत्र को बदनाम करने के लिए फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी की। उसने यू ट्यूब पर भी आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप शेयर की थीं। अदालत ने यह सजा ऐसे समय में सुनाई है, जब राजतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र समर्थकों का कई महीनों से आंदोलन चल रहा है।

मानवाधिकार संस्था के एक वरिष्ठ शोधकर्ता ने कहा है कि अदालत ने ऐसा निर्णय देकर संदेश दिया है कि राजतंत्र की आलोचना करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे ही कड़ा दंड दिया जाएगा। बैंकॉक पोस्ट के अनुसार, अदालत ने शुरुआत में शाही मानहानि में जेल की शर्तों के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए महिला को 87 साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, जब से महिला ने मुकदमे के दौरान मानहानि को कबूल किया था, उसकी सजा 43 साल और छह महीने हो गई। इससे पहले उसे 2018 में जमानत देने से पहले जांच के दौरान तीन साल और नौ महीने के लिए हिरासत में लिया गया था। सजा से उस अवधि को तब कम किया जाता है, जब केस बंद हो। 2015 में यूट्यूब पर 26 बार और फेसबुक पर तीन बार क्लिप अपलोड करने के आरोप में एंचन (परिवार का नाम) को गिरफ्तार किया गया था। यह क्लिप बनपोड्ज (छद्म नाम) नामक एक व्यक्ति की आवाज की रिकॉर्डिंग थी, जो राजशाही का कट्टर आलोचक था जो 2014 के सैन्य तख्तापलट से पहले और बाद में वेबसाइटों पर यूट्यूब और फाइलों को साझा करने वाली सक्रिय था, तब कंप्यूटर अपराध कानून का उल्लंघन करने के लिए एंचन पर भी आरोप लगाया गया था।

चीन ने दी अमेरिकी अधिकारियों पर प्रतिबंध की धमकी, हांगकांग में दखलंदाजी का लगाया आरोप

बीजिंग। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर पाबंदी पर चीन ने पलटवार किया है। चीन ने कहा कि वह भी अब हांगकांग में अनावश्यक हस्तक्षेप और पाबंदी लगाने वाले अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों के खिलाफ पाबंदी लगाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हुआ

चुनयिंग ने कहा कि अमेरिका हांगकांग में अनावश्यक रूप से अपनी टांग अड़ा रहा है। इसी के चलते उसने पचास लोकतंत्र समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद छह चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर पाबंदी लगाई है।

पाबंदी लगाने के मामले में बिना किसी अधिकारी का नाम लिए प्रवक्ता ने कहा कि अब चीन भी ऐसी ही कार्रवाई अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ करेगा। अमेरिका को हांगकांग और चीन के मसलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। ज्ञात हो कि 16 जनवरी को अमेरिका ने छह चीनी और हांगकांग अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। इस घटना के बाद हांगकांग के मामले में अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया था।

आप्रवासियों के लिए नागरिकता संबंधी बिल पेश करेंगे बाइडन, एक करोड़ 10 लाख को मिलेगी नागरिकता

वाशिंगटन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन अपने प्रशासन के पहले दिन एक आव्रजन विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। इस विधेयक में देश में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब एक करोड़ 10 लाख लोगों को आठ वर्ष के लिए नागरिकता देने का प्रविधान होगा। यह आव्रजन विधेयक ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों के विपरीत होगा।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद पेश किया जा सकता है विधेयक

विधेयक के संबंध में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि बाइडन के बुधवार को शपथ ग्रहण करने के बाद यह विधेयक पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर बाइडन ने आव्रजन पर ट्रंप के कदमों को अमेरिकी मूल्यों पर कठोर हमला करार दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि वह इस नुकसान की भरपाई करेंगे। इस विधेयक के तहत एक जनवरी 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों

की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यता पूरी करते हैं, तो उनके लिए पांच वर्ष के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन और वर्ष के लिए नागरिकता मिल सकती है। कई मुस्लिम देशों से लोगों के आगमन पर रोक समेत आव्रजन संबंधी ट्रंप के कदमों को पलटने के लिए बाइडन द्वारा त्वरित कदम उठाए जाने की संभावना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिणामों को पलटने के लिए अमेरिकी संसद पर हमला एक चौंकाने वाली घटना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी लोकतंत्र इस संकट से ना केवल मजबूत होकर उभरेगा और देश में एक बार फिर कानून का शासन स्थापित होगा। इस संबंध में जारी एक बयान में 23 विशेषज्ञों ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन जारी बयान में ना केवल इस हमले की निंदा की गई बल्कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए जाने का भी आह्वान किया गया है। विशेषज्ञों ने उन लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की, जो इस महत्वपूर्ण क्षण में लोकतंत्र, समानता और कानून के शासन के साथ खड़े हैं। उधर, अमेरिकी संसद पर हुए हमले के मामले में एफबीआइ ने टेक्सास से दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

नागरिकता से जुड़े आंकड़ों को लेकर आलोचना झेल रहे अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के निदेशक स्टीवन डिलींघम ने कहा कि वह बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। डिलिंघम का पांच वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष के अंत में समाप्त होने वाला था।

चीनी हमले की आशंका में ताइवान का युद्धाभ्यास

ताइपे। चीन के हमले की आशंका में ताइवान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को सेना का युद्धाभ्यास शुरू किया है। युद्धाभ्यास में वह टैंक, मोर्टार और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ताइवान के मेजर जनरल चेन चोंग जी बताया कि ताइपे के दक्षिण स्थित सेना के हुको बेस पर यह युद्धाभ्यास चल रहा है। हमें यह मतलब नहीं है कि ताइवान की जलसंधि में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने द्वीप और इसकी जमीन की सुरक्षा जरूर करेंगे। हमारी सेना का युद्धाभ्यास सभी पक्षों को यह बताता है कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं।

ज्ञात हो कि ताइवान की राष्ट्रपति साइ इंग वेन पहले ही कह चुकी हैं कि ताइवान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अमेरिका से बड़ा रक्षा समझौता भी किया है, जिसके तहत उसे एफ-16 विमान, हथियारयुक्त ड्रोन, रॉकेट सिस्टम, हार्पून मिसाइल उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान की सैन्य उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री और पनडुब्बियों के निर्माण का कार्य भी तेज किया है। ताइवान को लगातार चीन की धमकियों के देखते हुए ताइवान इस तरह की तैयारी कर रहा है।

दिल्ली सरकार ने 307 खिलाड़ियों को दिए 7.48 करोड़

- अंडर-14 से अंडर-17 तक के खिलाड़ियों को 2 से 3 लाख तक की प्रोत्साहित राशि दी
- क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, टेनिस व कबड्डी सहित 18 खेलों के खिलाड़ियों को दिया जाता है लाभ

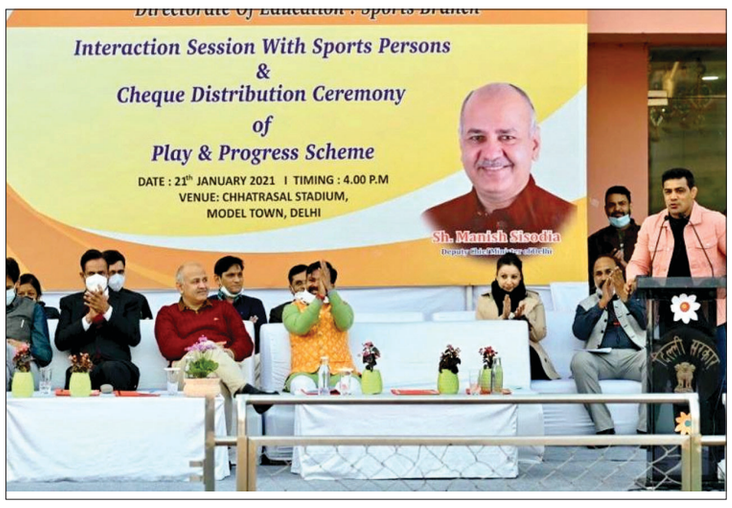

नई दिल्ली, प्रफुल्ल राय(शिवालिक)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली की खेल प्रतिभाओं से स्पोर्ट्स में बड़ी कामयाबी हासिल करके दिल्ली और देश का नाम ऊंचा करने का आह्वान किया। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्होंने 307 खिलाड़ियों के बीच 7.48 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रशिक्षण के साथ ही उनके अच्छे पोषण का भी ध्यान रख रही है। शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक खेल भी है, तथा पिछले 3 सालों से दिल्ली 'स्कूल गेम्स' में प्रथम स्थान पर कायम है।

यही कारण रहा है कि केंद्र सरकार के नीति आयोग ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश में सबसे अव्वल बताया है। यह पूरी दिल्ली के लिए गर्व की बात है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य सरकारें मेडल लाने के बाद खिलाड़ियों पर ध्यान देती हैं, जबकि दिल्ली सरकार अपने होनहार खिलाड़ियों के संघर्ष के समय उनकी जरूरतों को पूरा कर उन्हें मेडल जीतने लायक बनाने में मदद करती है।

सिसोदिया ने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली सरकार अंडर-14 के खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए तथा अंडर-17 के खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। अंडर-17 के बाद खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सालाना 16 लाख रुपए की आर्थिक मदद करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि हर स्टूडेंट किसी एक खेल से जरूर जुड़े। उनका यह भी सपना है कि हर प्रतिभावान खिलाड़ी को सरकार की तरफ से जरूरी सहायता मिले। इसीलिए हमने खिलाड़ियों को मैडल जीतकर लाने लायक बनाने वाली यह अनोखी योजना शुरू की है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के माध्यम से देश में एकजुटता आती है। कोई खिलाड़ी जब देश के लिए पदक लाता है तो सारे देश का सर गर्व से उठ जाता है। उल्लेखनीय है दिल्ली सरकार ने राज्य स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के खिलाड़ियों के लिए %प्ले एंड प्रोग्रेस% योजना चला रखी है। इसमें अंडर-14 से अंडर-17 तक के खिलाड़ियों को आज 2 से 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहित राशि दी गई। इस योजना के तहत क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, टेनिस व कबड्डी सहित 18 खेलों के खिलाड़ियों को लाभ दिया जाता है। वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत 357 स्कूली खिलाड़ियों को 8.72 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई थी।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद को काफी महत्व दिया है। इसके कारण राष्ट्रीय स्कूली खेलों में दिल्ली के स्कूलों को सर्वाधिक मैडल मिलते हैं। वर्ष 2017-18 में 508 गोल्ड, 303 सिल्वर, 273 ब्रॉन्ज, कुल 1084 पदक मिले। वर्ष 2018-19 में 484 गोल्ड, 306 सिल्वर, 286 ब्रॉन्ज, कुल 1076 पदक मिले। वर्ष 2019-20 में 408 गोल्ड, 285 सिल्वर, 302 ब्रॉन्ज, कुल 995 पदक मिले। साथ ही, 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020' थर्ड एडिशन में दिल्ली के खिलाड़ियों ने 39 गोल्ड, 36 सिल्वर, 47 ब्रॉन्ज मैडल लाए। समारोह में ओलिंपिक विजेता सुशील कुमार के साथ ही एच. राजेंद्र प्रसाद सचिव, शिक्षा विभाग, उदित प्रकाश निदेशक, खेल एवं शिक्षा तथा न्यूट्रिशनिस्ट रूचिका सोढ़ी भी मौजूद थे।

केजरीवाल सरकार ने किया 26 हजार करोड़ का घोटाला : भाजपा

(रविशंकर तिवारी)

दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों पर चर्चा के लिए सत्र बुलाए दिल्ली सरकार

अरविन्द केजरीवाल ने अपने दो करीबी नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के 26,000 करोड़ रुपए डकार लिए : आदेश गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार पर 26 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का अरोप लगाया है।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रैस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने अपने दो करीबी नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता का 26,000 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सिलसिलेवार दस्तावेज मीडिया को दिखाए। प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार, मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हरीश खुराना और मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर मौजूद थे। आदेश गुप्ता ने कहा दिल्ली जल बोर्ड पिछले 6 सालों में दलाली जल बोर्ड बन गया है। मात्र पांच वर्षों में अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। दिल्ली के टैक्स पेयर का 26000 करोड़ रुपए हड़पने के बाद केजरीवाल सरकार डकार तक नहीं ले रही है।

आदेश गुप्ता ने दिल्ली वित्त निगम और सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के खातों से पिछले पांच सालों में 26,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के खातों में स्थनांतरित किए गए, लेकिन उसका हिसाब केजरीवाल, सत्येन्द्र जैन या राघव चढ्ढा देने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने हर घर में नल से जल देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक दिल्ली के एक-चौथाई भाग को पीने के पानी की पाइप लाइन के दर्शन तक नहीं हुए हैं।

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जल के घोटालों की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुलाएं और दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों पर चर्चा कराएं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यों के साथ हैं, इसलिए दिल्ली की जनता को वो साफ करें कि आखिर 26,000 करोड़ का जो घोटाला किया गया है, उन पैसों को किन-किन मदों में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की नियत यदि साफ है तो उन्हें इन पैसों का हिसाब देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में कोरोना वायरस रिकवरी दर 97.95 फीसदी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामले अब 2,100 के करीब रह गए हैं। राहत की एक और बात यह है कि राजधानी में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ कर 97.95 फीसदी पहुंच गई है। दिल्ली में बुधवार को सक्रिय मामले 187 और घटकर अब 2,147 रह गये। राजधानी में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में यह कमी दर्ज की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में 228 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,33,049 तक पहुंच गयी है जबकि 405 और मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 6,20,128 हो गई।

घोषणा के बावजूद दिल्ली सरकार ने नहीं दिए 938 करोड़ : महापौर

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धृतराष्ट्र बने हुए हैं, निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार ने अभी तक 938 करोड़ नहीं दिए है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगभग एक हफ्ते पहले प्रैस वार्ता कर यह कहा था कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार ने निगम को 938 करोड़ रूपय जारी कर रही है। मगर अभी तक निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार से एक पैसा भी दिल्ली नगर निगम को नहीं मिला है। महापौर जय प्रकाश ने कहा की दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के लिए घोषणा तो कर दी मगर दिल्ली नगर निगम को 938 करोड़ रूपय नहीं दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की इसी निति की वजह से आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम वित्तीय संकट की स्थिती से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थान है और नगर निगम कों आर्थिक सहायता प्रदान करना राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जनवरी महीने में जारी होने वाली तीसरी तिमाही का फंड भी अभी तक नहीं दिया है वो कब दिया जाएगा इसकी भी जानकारी दे दिल्ली सरकार।

पूर्वी निगम में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के राजभाषा अनुभाग द्वारा गुरुवार को निगम सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत स्वच्छता ही सेवा और प्लास्टिक मुक्त अभियान पर एक ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए स्वच्छता ही सेवा, कचरा अलग करना तथा प्लास्टिक को ना कहे तीन विषय निर्धारित किए गए थे। काफी संख्या में निगमकर्मियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतिभागियों ने वाटर, पोस्टर, पेस्टल और एकरिलिक रंगों से अपने चित्रों में जान भरी। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर, निर्मल जैन, उप-महापौर एवं हिन्दी समिति के अध्यक्ष, हरि प्रकाश बहादुर, स्थायी समिति अध्यक्ष, सत्यपाल सिंह, अपर आयुक्त, अल्का शर्मा तथा उपायुक्त के.डी वर्मा भी उपस्थित थे।

आप विधायक ने डीडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर निकाला मार्च

(प्रवीण कुमार सिंह)

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के करोल बाग से विधायक विशेष रवि ने फेथ अकेडमी स्कूल द्वारा कथित अवैध रूप से कब्जा की गई स्पोर्ट्स कांप्लेक्स की जमीन को खाली नहीं कराने पर डीडीए के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। आईएनए मेट्रो स्टेशन के गेट दो पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और डीडीए के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विधायक विशेष रवि ने स्थानीय निवासियों के साथ डीडीए के वीसी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और जमीन को शीघ्र खाली कराने की मांग की। डीडीए के वीसी ने स्कूल द्वारा कब्जाई गई जमीन को जल्द से जल्द खाली कराने का आश्वासन दिया है। विधायक विशेष रवि ने कहा कि अगर जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है, तो आम आदमी पार्टी स्थानीय लोगों के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने कहा कि करोल बाग के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। इसमें दो एकड़ जमीन पर फेथ अकेडमी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। जमीन को खाली कराने के लिए स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन डीडीए द्वारा जमीन को खाली नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने भी 4 मई 2017 को डीडीए को आदेश देते हुए कहा था कि फेथ अकेडमी द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराया जाए ओर स्कूल से अवैध रूप से जमीन कब्जा करने के लिए जुर्माना भी वसूला जाए।

खराब श्रेणी में रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि राजधानी में अधिकतम तापमान 19 डिगी सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री नीचे था जबकि न्यूनतम तापामान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री ऊपर था।

राष्ट्रीय राजधानी में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 रिकॉर्ड किया जो कि बहुत खराब श्रेणी है। दिल्ली की 24 घंटे की वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को 283 रही जो की खराब श्रेणी थी। मंगलवार को सूचकांक 404 था जो की गंभीर श्रेणी में आता है, सोमवार और रविवार को 372 और 347 था जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक शून्य से 50 तक अच्छी, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में मानी जाती है।

सांई सेवा संस्थान ट्रस्ट ने गरीबों को बांटे कंबल और भोजन

नई दिल्ली, (विवेक राय)। समाज में गरीबी में जीवन यापन कर रहे निर्धन, असहाय, मजदूरो को ठंड के महीने में बचाव के लिए मदद की आवश्यकता होती है। कड़ाकेकी ठंड पड़ने से किसी के पास गर्म वस्तुएं न होने के कारण लोगों की जान के लालेपड़ जाते हैं। और इसका असर गरीबों, चैकीदारों, सड़क के किनारे रहने वाले, और रिक्शाचालकों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। समाज में जो भी सक्षम हैं वह अपने-अपनेतरीके से ऐसे लोगों की मदद करें और यह बहुत ही पुनीत कार्य है। यह बात साईं सेवासंस्थान ट्रस्ट के संस्थापक और समाजसेवी निखिल कुमार सिंह ने चिल्ला गांव स्थित साईं मंदिर में कंबल व भोजन वितरण करने के दौरान कही। गुरुवार को निखिल सिंह ने गरीबों में 200 गर्म कंबल दान किये साथ ही मौजूद हजार असहाय लोगों के लिए भोजन का भी आयोजन किया।

14 घंटे में पुलिस ने सुलझाया 20 करोड़ की चोरी का मामला

मालिक को सबक सिखाने के लिए कर्मचारी ने ही दिया था वारदात को अंजाम

नई दिल्ली, 21 जनवरी नई दिल्ली। कालकाजी इलाके में हुई इस साल की सबसे बड़ी चोरी को कालकाजी थाना पुलिस ने 14 घंटे में सुलझा दिया । पुलिस ने दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वैलरी और 23 हजार रुपए बरामद किए हैं। आरोपी 25 वर्षीय शेख नूर रहमान ने बताया कि वह कम्पनी के मालिक से गुस्साए था और उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसने यूट्यूब और बॉलिवुड़ की एक फिल्म देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात करने से पहले उसने पूरी तैयारी की थी, जिसमें उसने 50 हजार रुपए से ज्यादा खर्च भी किए। फिलहाल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त आर.पी मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह कालकाजी थाना पुलिस को अंजलि ज्वेलर्स के शोरूम में चोरी की सूचना मिली। सूचना के बाद पहुंच कालकाजी थाना एसएचओ सुभाष, एसआई विनोद, एसआई नवीन, एएसआई प्रवीण के साथ मौके पर पहुंचे। जहां शिकायतकर्ता अरिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि वह मंगलवार रात को अपना शोरूम बंद कर घर गए थे। अगले दिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शोरूम के प्रथम मंजिल पर चोरी हुई थी। चोर 25 किलोग्राम सोना (20 करोड़ रुपए) की चोरी कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले में स्थानीय पुलिस, स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह, इंस्पेक्टर लव अत्रे सहित आठ पुलिस इंस्पेक्टरों की टीम बनाई और जांच शुरू की। फोन लॉकेशन से पकड़ा गया आरोपी पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज जब्त की। फुटेज की जांच में पुलिस ने पाया कि एक युवक पीपीई किट पहने शोरूम में घुस और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। इस फुटेज से पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता के यहां काम करने वाले सभी लोगों की जानकारी जुटाई। इसमें सामने आया कि शोरूम में टैक्निशियन का काम करने वाले एक युवक ने दस दिन पहले अपने घर बंगाल जाने के लिए छुट्टी ली है। पुलिस ने शोरूम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सीडीआर और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकाल कर जांच की। जिसमें सामने आया कि शोरूम का टैक्निशियन शेख नूर रहमान घर जाने के लिए छुट्टी लेकर गया था। लेकिन उसका फोन दिल्ली के करोल बाग में एक्टिव है। पुलिस ने शेख नूर रहमान की लॉकेशन निकाल कर उसे करोल बाग से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

युवा निर्माण वाहिनी ने तांडव वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

नई दिल्ली, 21 जनवरी नई दिल्ली। युवा निर्माण वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज को प्रतिबंधित करने की मांग की तथा सैफ अली खान के पोस्टरों को जलाया। युवा निर्माण वाहिनी द्वारा तांडव वेब सीरीज के विरोध में विजय चौक लक्ष्मी नगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तांडव वेब सीरीज को बैन करने तथा इसे बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही एवं गिरफ्तारी की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, प्रमुख कलाकार सैफ अली खान व मोहम्मद जीशान अय्यूब आदि कलाकारों के पोस्टर जलाए तथा पोस्टरों को जूते चप्पलों से पीटा गया और नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के पश्चात वाहिनी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी नगर थाने पहुंचकर सैफ अली खान एवं अन्य कलाकारों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई, जिसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

आयोजन स्वयं प्रकाश की स्मृति में वेबिनार का हुआ आयोजन

सौ रंगों की भाषाओं वाले कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश : असगर वजाहत

(एजेंसी)

नई दिल्ली। 'स्वयं प्रकाश की कहानियां, कहानी के कहानीपन को तोड़ती हैं। उनकी भाषा कभी संस्मरण की भाषा का रूप ले लेती है तो कभी रेखाचित्र, डायरी और अख़बार की भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। उनकी भाषा के अनेक रंग-बिरंगे रूप हैं। स्वयं प्रकाश के कहानियों की उपलब्धि उनकी भाषा के यही सौ रंग हैं।' सुप्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार असग़र वजाहत ने स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास द्वारा स्वयं प्रकाश की 74 वीं जयंती पर आयोजित वेबिनार में उक्त विचार व्यक्त किए। प्रो. वजाहत ने 'कहानी की भाषा' विषय पर वेबिनार में क्रमशः भाषा, कहानी की भाषा और स्वयं प्रकाश की कहानियों की भाषा पर प्रकाश डाला।

उन्होंने सर्वेश्वर दयाल और रघुवीर सहाय जैसे कवि-कहानीकारों के भाषिक प्रयोगों और उनके कहानियों के भाषा की सूक्ष्मताओं के बारे में भी बताया। प्रो वजाहत ने स्वयं प्रकाश जी की कहानियों की भाषिक जीवंतता को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वयं प्रकाश जिंदा भाषा के कहानीकार हैं। अपनी कहानियों में उन्होंने चमकती हुई,खिलती हुई भाषा का प्रयोग किया है।

अपने समय के अन्य कहानीकारों की भांति वे भाषा के चमत्कारिक और कलात्मक प्रयोग के लोभ में नहीं फंसते और पूरी कहानी में अपनी भाषा को अद्वितीय ढंग से विश्वसनीय और जीवंत बनाए रखते हैं। व्याख्यान के समाहार में प्रो. वजाहत ने स्वयं प्रकाश की तीन कहानियों, 'बलि', 'गौरी का गुस्सा' और 'पार्टीशन' का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कैसे उनकी कहानी के पात्रों की भाषाएं व्याकरण की बंदिशों को तोड़ते दिखाई देते हैं। उन्होंने संवाद, कथ्य, परिवेश और पात्रों की भाषा के परस्पर संबंधों को स्पष्ट किया और कहानी में मौजूद संवाद और वर्णन के बीच के सूक्ष्म अंतर को भी समझाया।

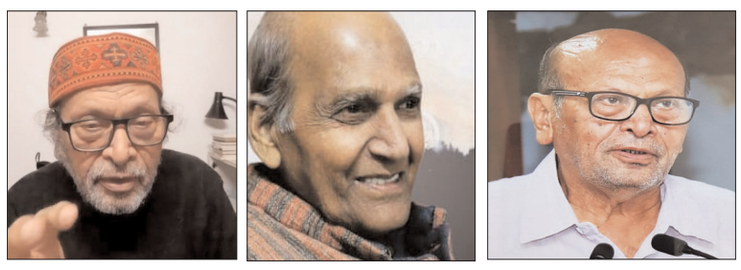

प्रो. वजाहत ने 'कहानी की भाषा' विषय पर स्वयं प्रकाश की कहानियों की भाषा पर प्रकाश डाला

वेबिनार में प्रो वजाहत ने आनन्द प्रकाशन, कोलकाता से डॉ कामेश्वर सिंह के संपादन में सद्य प्रकाशित पुस्तक 'स्वयं प्रकाश की सर्वश्रेष्ठ कहानियां' का लोकार्पण भी किया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में न्यास के अध्यक्ष प्रो मोहन श्रोत्रिय ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं के प्रचार प्रसार के प्रति न्यास की प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ विशाल विक्रम सिंह ने स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास का विस्तृत परिचय देते हुए उसके सदस्यों के नामों की घोषणा की, जिनमें वरिष्ठ आलोचक और संपादक प्रो मोहन श्रोत्रिय (अध्यक्ष), आलोचक डॉ दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, कवि राजेश जोशी, कवि और आलोचक प्रो आशीष त्रिपाठी, आलोचक और संपादक डॉ पल्लव (सचिव), श्रीमती अंकिता सावंत और श्रीमती अपूर्वा भटनागर शामिल हैं। न्यास द्वारा प्रतिवर्ष एक सम्मान भी दिया जाएगा। अंत में स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास के गठन के उद्देश्यों और उसकी प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालते हुए, न्यास के सचिव और बनास जन पत्रिका के संपादक डॉ पल्लव ने श्रोताओं और मुख्य वक्ता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। फेसबुक पर प्रसारित इस वेबिनार में स्वयं प्रकाश जी के प्रशंसकों, पाठकों के साथ-साथ देश भर के अनेक वरिष्ठ साहित्यकारों ने भागीदारी की।

संपादकीय

सिर्फ शब्द न रह जाए संविधान

जमशेदपुर कई अर्थों में बड़ा दिलचस्प शहर है। यहां 1907 में टाटा औद्योगिक घराने की नींव रखने वाले जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा ने इलाके के पहले बड़े कारखाने टिस्को की स्थापना के साथ ही भविष्य के एक बड़े शहर की शुरुआत भी की थी। आज अपनी सुदृढ़ नागरिक सुविधाओं, फुटबॉल और शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त यह शहर मुझे इसके नागरिकों की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहसों में सक्रिय भागीदारी और गहरी समझ के लिए उल्लेखनीय लगता है। इस शहर की मेरी चौथी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम के सिलसिले में थी, जिसका विषय शुरू में तो मुझे घिसा-पिटा लगा, पर वहां जाकर शहरियों की भागीदारी और जुड़ाव देखकर समझ में आया कि हाशिए पर अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों या औरतों के लिए ऐसे विमर्श क्या अर्थ रखते हैं? विषय भारतीय संविधान और उसके चलते देश की अखंडता या संप्रभुता को बचाने से जुड़ा था। आयोजक संस्था का नाम भी 'देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान' है। विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े ये लोग संविधान को लेकर कितने चिंतित हैं, इसे इनके पिछले कुछ वर्षों के कार्यक्रमों की सूची देखकर समझा जा सकता है। कुछ ही दिनों में हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। हाल-फिलहाल बहुत कुछ ऐसा घटा है, जिसके चलते नागरिकों को स्मरण कराना जरूरी है कि संविधान की हिफाजत की शपथ लेते रहना सिर्फ औपचारिकता नहीं है। आजादी के फौरन बाद मुसलमानों की एक पस्त भीड़ के सामने बोलते हुए मौलाना आजाद ने कहा था कि उन्हें तब तक अपनी हिफाजत की चिंता नहीं करनी चाहिए, जब तक 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान सुरक्षित है। अब तो देश के दूसरे हाशिए के समुदायों को भी समझ में आ गया है कि अगर संविधान नहीं बचा, तो उनके एक सभ्य मनुष्य के रूप में जीने की संभावना भी नहीं बचेगी। इस संविधान के बनने और उसके जनता द्वारा स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया को बार-बार याद किए जाने की जरूरत है। 1947 से 1949 के बीच नई दिल्ली की संविधान सभा में जो कुछ घट रहा था, वह किसी शून्य से नहीं उपजा था। यह असाधारण जरूर था, पर अप्रत्याशित तो बिल्कुल नहीं कि रक्तरंजित बंटवारे के बीच काफी लोगों ने मान लिया था कि हिंदू और मुसलमान, दो अलग राष्ट्र हैं, इसलिए साथ नहीं रह सकते। तब संविधान सभा ने देश को ऐसा संविधान दिया, जो एक उदार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परिकल्पना करता है। यह अप्रत्याशित इसलिए नहीं कि देश की आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों से परिचालित हो रही थी, वे आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता की ही उपज थे। अस्पृश्यता या स्त्री-पुरुष समानता जैसे प्रश्नों पर संविधान सभा की दृष्टि एक आधुनिक दृष्टि थी और इसके चलते भारतीय समाज में दूरगामी परिवर्तन होने जा रहे थे। इसी तरह, एक करोड़ से अधिक लोगों के विस्थापन और विकट मार-काट के बीच भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अर्जित एकता की भावना ने ही इस धर्मनिरपेक्ष संविधान को संभव बनाया।

यह संविधान 26 नवंबर, 1949 को बन तो गया, पर इसे बनाने वाली सभा ही जनता से सीधे नहीं चुनी गई थी और इसकी वैधता के लिए जरूरी था कि इस पर जन-स्वीकृति की मोहर लगवाई जाए। इस जिम्मेदारी को निभाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ 1952 के पहले आम चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। चुनाव के पहले 1951 में उन्होंने देश भर में घूम-घूमकर 300 सभाएं कीं। जालंधर से शुरू हुई उस शृंखला में उनका एक ही एजेंडा था, लोगों को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए तैयार करना। हर सभा में वह इस सवाल से अपना कार्यक्रम शुरू करते, देश बंटवारे के साथ आजाद हुआ है, हमारे बगल में एक धर्माधारित इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी एक हिंदू राज बना लेना चाहिए? इन सवालों के जवाब वह खुद अगले डेढ़ घंटे तक आसान हिन्दुस्तानी में देते। वह लगभग अशिक्षित श्रोताओं को अपने तर्कों से कायल करके ही भाषण समाप्त करते कि कैसे देश की एकता, अखंडता और तरक्की के लिए एक धर्मनिरपेक्ष भारत जरूरी है। समय ने उन्हें सही साबित किया। मजहब के नाम पर बना पाकिस्तान 25 वर्षों में ही टूट गया और तमाम हिचकोलों के बावजूद भारत एक मजबूत राह पर आगे बढ़ रहा है। जालंधर को पहले सभा-स्थल के रूप में चुनना नेहरू की आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार करने की प्रवृत्ति का ही परिचायक था। गौर कीजिए, जालंधर की उनकी सभा के अधिसंख्य श्रोता वे हिंदू और सिख थे, जो कुछ ही दिनों पहले बने पाकिस्तान से अपने प्रियजनों और जीवन भर की जमा-पूंजी गंवाकर वहां पहुंचे थे। नेहरू जानते थे कि अगर इन हिंसा पीड़ितों को वह समझा सके कि धार्मिक कट्टरता बुरी चीज है, तो बाकी देश में उनका काम आसान हो जाएगा। यही हुआ भी, चुनावी नतीजों ने एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को वैधता प्रदान कर दी। जमशेदपुर के कार्यक्रम में न्यायविद फैजान मुस्तफा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। एक अच्छे संविधान के बावजूद अमेरिका में ट्रंप के उकसावे पर भीड़ संसद पर चढ़ दौड़ी, इस स्थिति में सारी सदिच्छाओं का क्या होगा? वहां कम से कम संस्थाओं में इतना दम तो है कि प्रारंभिक झटके के बाद उन्होंने अपने राष्ट्रपति का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। क्या हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं? लोकतंत्र में जरूरी है कि विवाद या तो बातचीत से हल हों या फिर संविधान के दायरे में न्यायिक समीक्षा द्वारा, पर हाल का किसान आंदोलन इस मामले में निराशाजनक है कि सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजने की बात की। संविधान की रोशनी में सरकार को खुद आगे बढ़कर समाधान की तलाश करनी चाहिए। हमारे तंत्र पर ऐसे खतरे तब तक मंडराते रहेंगे, जब तक हम संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता या कानून के सामने सबकी बराबरी जैसे मूल्यों को अपनी जीवन पद्धति का अंग नहीं बनाएंगे। संविधान में दर्ज शब्द कितने खोखले हो सकते हैं, यह हमसे बेहतर कौन जान सकता है?

प्रवीण कुमार सिंह

देश में उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की कवायद, ताकि सबके लिए उच्च शिक्षा पाना हो आसान

यहां एक और बात का उल्लेख जरूरी है कि सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन फाइनांसिंग एजेंसी (एचइएफए) द्वारा लोन मुहैया कराए जाने की बात कही है। लेकिन लोन आधारित शिक्षा व्यवस्था की यह अवधारणा ही अपने आप में संकटपूर्ण है। इसका नतीजा यह होगा कि शिक्षा निजी खिलाड़ियों एवं संस्थानों के नियंत्रण में रहेगी और यह मुनाफा एवं व्यापार का जरिया बन जाएगी। महंगी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन पाने में असमर्थ बच्चे बड़ी संख्या में इस व्यवस्था के कारण उच्च शिक्षा की सीढ़ी पर पांव ही नहीं रख पाएंगे।

देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए एचईसीआइ यानी भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की कवायद की जा रही है। हालांकि इसके गठन के लिए जिन तीन संस्थानों को विघटित किया जाएगा, उनमें से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काफी सशक्त संस्थान है। वर्ष 1956 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में स्थापित यह संस्थान उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने के साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने व शिक्षण संस्थाओं के समन्वय, परीक्षा और शोध के मानकों के निर्धारण समेत उनको लागू करवाने तथा उच्च शिक्षा के न्यूनतम मानकों से जुड़े नियम बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम करता रहा है। यूजीसी समय समय पर उन संस्थानों की सूची भी प्रकाशित करता रहा है, जो इन मानकों को पूरा नहीं करते और इस आधार पर यह उनकी मान्यता रद करता है। यह सच है कि इन संस्थानों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की शक्तियां यूजीसी के पास नहीं हैं और अनिवार्य मानकों पर खरे न उतर पाने वाले या नियमों का उल्लंघन करने वाले इन संस्थानों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए इसे और अधिक शक्तियां दी जा सकती थीं। लेकिन अब इस आयोग को ही खत्म करने का फैसला ले लिया गया है।

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने की संस्तुति हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने अपने दस्तावेज में इस बात को रेखांकित किया है कि दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत खराब रहा है और इस दिशा में किए गए प्रयास नाकाफी रहे हैं। विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है। जैसे कुछ ही निकायों में शक्तियों

का अत्यधिक केंद्रीकरण, इन निकायों के बीच स्व-हितों का टकराव होना, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और इसे कामयाब करने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत चार स्वतंत्र सांस्थानिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है। इसमें पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (एनएचईआरसी) होगा जो उच्चतर शिक्षा के लिए एक रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण तो शामिल है, मगर चिकित्सकीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है। उच्च शिक्षा आयोग का दूसरा अंग होगा राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) जो उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन कुछ बुनियादी नियम-कायदों, सार्वजनिक स्व-प्रकटन, मजबूत एवं प्रभावी गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर करेगा। तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) होगा, जो पारदर्शी मानदंड के आधार पर फंडिंग का कार्य करेगा। चौथा विभाग सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) होगा, जो शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा।

इन तमाम सुधारों के जरिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दावा करती है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार होंगे जो उच्च शिक्षा में व्याप्त मौजूदा बिखराव को समाप्त कर उसे समेकित करने और बेहतर गवर्नेंस स्थापित करने में सशक्त सिद्ध होंगे। हालांकि बहुत सारे शिक्षाविद इस ढांचे में शक्तियों का और भी केंद्रीकरण व सांस्थानिक स्वायत्तता की जगह सरकारी हस्तक्षेप के बढ़ जाने का खतरा देख रहे हैं।

दरअसल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां काफी बड़ी हैं। खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार करती है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सकल नामांकन दर मात्र 26.3 प्रतिशत ही है, जो विकसित राष्ट्रों के मुकाबले काफी कम है। यह आंकड़ा चीन में 51 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 94, अमेरिका में 88, ब्रिटेन में 60, जर्मनी में 70 और कनाडा में 69 प्रतिशत है। यह आंकड़ा देश में उच्च शिक्षा की दशा को दर्शाने के लिए काफी है। इसे ठीक करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की जरूरत है, जिसे संस्थानों की स्वायत्तता को कायम रखकर ही किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों का बोलबाला भी बढ़ता जा रहा है, जिसने लगभग 70 फीसद हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। इन निजी संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता का मामला अभी तक संदेह के घेरे में है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने गुणवत्ता के लिहाज से केवल सरकारी मदद से चलनेवाले विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान ही टक्कर ले पाते हैं। इन संस्थानों को और ज्यादा प्रशासनिक स्वायत्तता एवं सरकारी आर्थिक मदद देकर मजबूत किया जा सकता है। मगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस दिशा में किसी ठोस सुझाव का अभाव दिखता है। इसके विपरीत इन संस्थानों को नए किस्म के पाठ्यक्रम चलाकर संसाधन जुटाने को बाध्य किया जा रहा है। इसका मतलब विश्वविद्यालय बच्चों की फीस के बलबूते संचालित किए जाएंगे। ऐसे में देश के पिछड़े इलाकों, गरीब परिवारों एवं समाज के शोषित तबकों से आने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा पाना और मुश्किल हो जाएगा।

यहां एक और बात का उल्लेख जरूरी है कि सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन फाइनांसिंग एजेंसी (एचइएफए) द्वारा लोन मुहैया कराए जाने की बात कही है। लेकिन लोन आधारित शिक्षा व्यवस्था की यह अवधारणा ही अपने आप में संकटपूर्ण है। इसका नतीजा यह होगा कि शिक्षा निजी खिलाड़ियों एवं संस्थानों के नियंत्रण में रहेगी और यह मुनाफा एवं व्यापार का जरिया बन जाएगी। महंगी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन पाने में असमर्थ बच्चे बड़ी संख्या में इस व्यवस्था के कारण उच्च शिक्षा की सीढ़ी पर पांव ही नहीं रख पाएंगे।

अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझे जाने वाले एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति के लिए ऋण नीति में बदलाव की आवश्यकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की सफलता एमएसएमई सेक्टर पर आधारित है और उसके सहारे ही मेक फॉर वर्ल्ड और वोकल फॉर लोकल का स्वप्न साकार करने का प्रयास है। भारत की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है जो 12 करोड़ रोजगार पैदा करता है। निर्यात में भी इस सेक्टर का योगदान करीब 50 प्रतिशत है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसी एमएसएमई की स्थापना और प्रसार के लिए कुछ प्रमुख सरकारी बैंक उनको गिरवी परिसंपत्ति के मूल्य के अनुपात में उचित ऋण राशि स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप विस्तार के लिए ये उद्योग पर्याप्त धनराशि से वंचित रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण बैंकों में गिरवी रखे जाने वाली परिसंपत्ति मूल्यांकन का कोई निर्धारित फार्मूला नहीं होना है। हालांकि भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है और आइबीबीआइ (इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया) द्वारा मूल्यांकन मानक तैयार होने की प्रक्रिया में है।

यद्यपि ऋण मंजूर करने से पूर्व बैंक आवेदनकर्ता के व्यवसाय के सफलता की संभावना और उसकी साख पर भी ध्यान देता है। फिर भी, मुख्य रूप से गिरवी रखे जाने वाली परिसंपत्ति के मूल्य के आधार पर ही ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण राशि की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक भी है। अतः सामान्यतया बैंक गिरवी परिसंपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर ही ऋण स्वीकृत करते रहे हैं। साधारण शब्दों में किसी निश्चित समय पर परिसंपत्ति को पर्याप्त प्रचार-प्रसार के बाद बेचने पर जो मूल्य मिलता है, उसे बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ अन्य बैंक रियलाइजेबल वैल्यू को ऋण राशि निर्धारित करने का आधार बना रहे हैं और रियलाइजेबल वैल्यू को परिसंपत्ति के मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग 15 प्रतिशत कम मान रहे हैं। जहां पहले 100 रुपये बाजार मूल्य के आधार पर 75 रुपये का ऋण देते थे, वहीं अब यह वैल्यू केवल 85 रुपये मान कर, उस रियलाइजेबल वैल्यू का 75 प्रतिशत राशि अर्थात केवल 63.75 रुपये ही ऋण के रूप में स्वीकृत कर रहे हैं। इस प्रकार ऋण आवेदनकर्ता को 100 रुपये मूल्य की संपत्ति के एवज में केवल 63.75 रुपये की ऋण राशि ही प्राप्त हो पा रही है, जबकि यह राशि 75 रुपये होनी चाहिए।

वर्ष 2015 से पहले बैंकों में रियलाइजेबल वैल्यू जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। जुलाई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एनपीए के विरुद्ध प्रोविजनिंग के लिए एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें रियलाइजेबल वैल्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की थी। वास्तव में इस शब्द के पीछे आरबीआइ की मंशा थी कि बाजार मूल्य का वास्तविक (रियलिस्टिक) और सही मूल्यांकन किया जाय, जो बंधक संपत्ति को बेचने पर प्राप्त हो सके, न कि बढ़ी हुई कीमत आंकी जाए। पूर्व में बैंकों ने बंधक की गई संपत्तियों का ज्यादा मूल्यांकन करते हुए ऋण स्वीकृत किए थे और ऋण वसूली न होने की सूरत में सरफेसी एक्ट (सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002) के तहत गिरवी संपत्ति विक्रय कर ऋण राशि वसूल करने का प्रयास करने लगे, लेकिन पूर्व में गलत या ज्यादा मूल्यांकन किए जाने के कारण उन्हें सही मूल्य नहीं मिले और नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व में ज्यादा मूल्यांकन की गलती को छिपाने के लिए बैंकों ने अपनी सुविधानुसार यह तर्क देकर कि जब संपत्ति बेची जाती है तो उन्हें बाजार मूल्य नहीं मिलता है, जो मूल्य उन्हें मिलता है, वो लगभग 15 प्रतिशत कम होता है और उसे उन्होंने रियलाइजेबल वैल्यू मान लिया। उल्लेखनीय है कि बाजार मूल्य का मतलब ही यह है कि संपत्ति बेचने पर जो कीमत (रियलाइज) प्राप्त हो।

भारतीय स्टेट बैंक व सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों का यह भी दावा है कि वे परिसंपत्ति मूल्य का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय मूल्य मानकों (आइवीएस) के अनुरूप करते हैं। हालांकि आइवीएस ने मार्केट वैल्यू, सिनर्जिस्टक वैल्यू व लिक्विडेशन वैल्यू जैसे शब्दों को तो परिभाषित किया है, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू को कहीं परिभाषित नहीं किया है। भारतीय लेखा मानक में नेट रियलाइजेबल वैल्यू को परिभाषित किया गया है जो बही-खातों में इन्वेंट्री का मूल्य दर्ज करने के लिए है, न कि अचल परिसंपत्ति मूल्य के रूप में। वास्तव में यहां नेट रियलाइजेबल वैल्यू का तात्पर्य यह है कि इन्वेंट्री को बेचने में होने वाले खर्च जैसे ब्रोकरेज या प्रचार का खर्चा काट कर जो पैसा हाथ में आए।

यदि भारतीय लेखा मानक द्वारा परिभाषित नेट रियलाइजेबल वैल्यू फार्मूले को ही बैंक भी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए भी लागू करें तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू बाजार मूल्य के 95 प्रतिशत से ज्यादा कम नहीं हो सकती, क्योंकि बंधक परिसंपत्ति को बेचने का खर्च जैसे ब्रोकरेज या प्रचार का खर्चा पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। अतः देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए बैंकों द्वारा रियलाइजेबल वैल्यू को बाजार मूल्य का 95 प्रतिशत मान कर ऋण स्वीकृत करना चाहिए।

ओली का नया दांव

पिछले हफ्ते नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञावाली की तीन दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने में काफी मददगार साबित हुई। लिपूलेख दर्रा, कालापानी और लिंपियाधुरा को लेकर पिछले साल हुए विवाद के बाद से नेपाल के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा थी। इस दौरान ज्ञावाली ने सीमा विवाद को बातचीत से हल करने की अपनी सरकार की सदिच्छा बार-बार दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल अपनी जमीन का इस्तेमाल अन्य देशों (मौजूदा संदर्भ में भारत) के खिलाफ नहीं होने देगा। इस यात्रा का एक अहम उद्देश्य भारत से कोरोना के टीके की आपूर्ति सुनिश्चित कराना भी था।

अच्छे पड़ोसी की अपनी भूमिका के अनुरूप भारत ने सभी मतभेदों को एक तरफ रखकर नेपाली विदेश मंत्री को आश्वस्त किया कि ये टीके नेपाल को प्राथमिकता से उपलब्ध कराए जाएंगे।

मगर इन सबके बावजूद जिन घरेलू राजनीतिक स्थितियों में ज्ञावाली का भारत दौरा हुआ है, उनकी अनदेखी करके दोनों देशों के रिश्तों के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले कुछ समय से अपने फैसलों और बयानों के जरिये जिस तरह का भारत विरोधी माहौल वहां पैदा किया, वह अभूतपूर्व है। चीन के पक्ष में झुका हुआ दिखने के मामले में भी उन्होंने अब तक की सारी हदें तोड़ दीं।

लेकिन दिलचस्प बात यह कि इस क्रम में वह न केवल नेपाली राजनीति में बल्कि सत्तारूढ़ नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी के अंदर भी किनारे पड़ते गए। पार्टी के सारे बड़े नेता उनके खिलाफ हो गए और उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार कोई और उपाय न देखकर ओली ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की और नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा कर दी। उनके विरोधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जिसका फैसला अभी नहीं आया है।

लेकिन इस बीच सत्तारूढ़ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी में विभाजन अवश्यंभावी लगने लगा और चीन की तरफ से इस संभावित विभाजन को टालने की कोशिश शुरू हुई। इसके लिए वहां से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल काठमांडू आया। इस प्रक्रिया में ओली को एक बार फिर अपना पद खतरे में दिखाई देने लगा है, लिहाजा उनकी कोशिश विदेश मंत्री को भेजकर भारत से रिश्ते सुधारने और चीन की ओर से बढ़ रहे दबाव का जवाबी बल तैयार करने की हो सकती है।

यह दिलचस्प है कि हाल तक भारत के खिलाफ चीन का मोहरा बने ओली अब चीन के खिलाफ भारत को मोहरा बनाने की फिराक में हैं। बेहतर होगा कि भारत के कूटनीतिज्ञ नेपाल के बरक्स दीर्घकालिक नजरिया अपनाकर आगे बढ़ें, उसकी घरेलू राजनीति के पचड़े से खुद को दूर ही रखें। भारत की कोशिश हर हाल में यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि अगले चुनावों में कोई भी दल भारत-नेपाल रिश्तों को मुद्दा न बनाए। दक्षिण एशिया में चीन की दखलंदाजी रोकने का अकेला तरीका यही है कि हम हर देश की घरेलू राजनीति के सभी पक्षों से सौहार्द कायम करें और द्विपक्षीय संबंधों में भरोसे और उम्मीद को सदाबहार बनाए रखें।

कोरोना की वैक्सीन को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं दुनियाभर के मुसलमान, टीके पर अनावश्यक है टीका-टिप्पणी

किसने सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग एक ही पंक्ति में खड़े होकर दूर-दूर हटकर नमाज पढ़ेंगे, जबकि ऐसा करने की पहले मनाही थी, लेकिन परिस्थिति ने इसे अमलीजामा पहनाया। इसके साथ ही किसने सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब जुमे की नमाज मस्जिद के बजाय घर में ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कोरोना महामारी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। कहने की जरूरत नहीं कि इंडोनेशिया में ही 2018 में उलेमा काउंसिल ने चेचक और रुबेला के टीकों में पोर्क जिलेटिन की मौजूदगी बताकर उन्हें 'हराम' कहा था, लेकिन नाजुक हालात को देखते हुए काउंसिल ने बच्चों को टीका लगवाने की छूट दे दी।

कोरोना रोधी वैक्सीन यानी टीके पर तमाम अटकलों और विवादों के बीच उसके 'हराम' और 'हलाल' होने के सवालों ने महामारी के संकट को और गहरा कर दिया है। भारत में वैक्सीन पर सियासी दलों की सियासत को धार देने में मुस्लिम समाज के इस कंफ्यूजन ने अहम योगदान दिया है। इस बहस की शुरुआत दक्षिण-पूर्वी एशियाई और मुस्लिम बहुल देशों इंडोनेशिया और मलेशिया में हुई, लेकिन धीरे-धीरे अब यह बहस भारत में भी पैर पसारने लगी है। दरअसल इस्लाम में उन उत्पादों को 'हलाल' कहा जाता है जिनमें 'हराम' चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। उदाहरण के लिए सूअर के मांस को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, इसलिए इससे बने उत्पाद इस्लाम में वर्जित बताए गए हैं। चूंकि मुस्लिम दुनिया में कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी से बने जिलेटिन के इस्तेमाल की चर्चा तेज हो गई है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमान धार्मिक कारणों से कोरोना वैक्सीन को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं।

हालांकि आमतौर पर वैक्सीन में सूअर की चर्बी से बने जिलेटिन का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन मौजूदा वैक्सीन में 'पोर्क जिलेटिन' के इस्तेमाल होने का कोई सुबूत नहीं है। कई वैक्सीन कंपनियों ने भी सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बहस के बीच फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका कंपनियों ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी वैक्सीन में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी हैं

जिन्होंने यह साफ नहीं किया है कि उनकी वैक्सीन में इसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं। यही कारण है कि मुस्लिम दुनिया में चिंता पसर गई है। वैक्सीन के हलाल सर्टिफिकेट की मांग केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं कर रहे हैं। यहूदी समुदाय में भी टीके के इस्तेमाल को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि वह भी सूअर के मांस से बने उत्पादों के इस्तेमाल को धार्मिक रूप से अपवित्र मानता है।

सवाल है कि जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन ऐसी चीज है जो जानवरों की चर्बी से प्राप्त होती है। इसे बनाने में सूअर के अलावा दूसरे जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सूअर की चर्बी से मिलने वाले जिलेटिन को 'पोर्क जिलेटिन' कहते हैं। दवा बनाने में इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। वैक्सीन में इसका इस्तेमाल एक स्टेबलाइजर की तरह करते हैं। यह जिलेटिन सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन स्टोरेज के दौरान सुरक्षित और असरदार बनी रहे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कई तरह के स्टेबलाइजर्स पर टेस्ट करती हैं। अब सवाल है कि अगर वैक्सीन में सूअर की चर्बी से बने जिलेटिन का उपयोग किया भी गया है तो क्या यह इतना बड़ा मुद्दा है? सवाल है कि इंसानी जिंदगी को बचाना अक्लमंदी का काम है या धर्म की आड़ में लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना? यह सच है कि इस्लाम में सूअर जैसे जानवर को कुरान ने 'हराम' करार दिया है। कुरान की सूरह (पाठ) मायदह की आयत नंबर-तीन में अल्लाह कहते हैं, 'तुम पर सूअर और मरे हुए जानवर का मांस खाना हराम है।' इसके अलावा कुरान में कई और जगह सूअर के मांस को 'हराम' करार दिया गया है, लेकिन इसी कुरान में खुदा ने इसकी काट भी बताई है। सूरह बकरा की आयत संख्या-173 में अल्लाह कहते हैं, 'कोई शख्स भयंकर भूख की हालत में बिल्कुल मजबूर हो जाए और उस हालत में हराम चीजों में से कुछ खा ले तो उसे गुनाह नहीं समझा जाएगा, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाला है।' इस आयत से साफ है कि अगर इंसान के पास जान बचाने के लिए कोई 'हलाल' रास्ता मौजूद न हो तो वह जान बचाने के लिए 'हराम' चीज का भी सहारा ले सकता है।

इन तर्कों के बीच एक यह तर्क भी पर्याप्त है कि खुदा की नजर में इंसानी जिंदगी की कीमत सबसे ज्यादा है। इसलिए वैक्सीन में चाहे किसी भी चीज का इस्तेमाल किया गया हो, जान बचाने के लिए इस तरह की बहसों में पड़े बगैर लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। इंसानी जिंदगी की कीमत ज्यादा है। उसे ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कतई मुनासिब नहीं होगा कि वैक्सीन में केवल पोर्क जिलेटिन के इस्तेमाल होने भर से लोगों को इससे वंचित कर दिया जाए। हमारे उलेमाओं को चाहिए कि कुरान में दी गई हर परिस्थितियों को सामने रखकर ही किसी नतीजे पर पहुंचें। एकतरफा व्याख्या करने से न केवल देश दुनिया, बल्कि कौम को भी नुकसान होता है। समझने की जरूरत है कि इस्लाम में नियमों को लचीला बनया गया है। किसने सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग एक ही पंक्ति में खड़े होकर दूर-दूर हटकर नमाज पढ़ेंगे, जबकि ऐसा करने की पहले मनाही थी, लेकिन परिस्थिति ने इसे अमलीजामा पहनाया। इसके साथ ही किसने सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब जुमे की नमाज मस्जिद के बजाय घर में ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कोरोना महामारी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। कहने की जरूरत नहीं कि इंडोनेशिया में ही 2018 में उलेमा काउंसिल ने चेचक और रुबेला के टीकों में पोर्क जिलेटिन की मौजूदगी बताकर उन्हें 'हराम' कहा था, लेकिन नाजुक हालात को देखते हुए काउंसिल ने बच्चों को टीका लगवाने की छूट दे दी। इससे नुकसान यह हुआ कि शुरुआत में बने माहौल के चलते बड़ी संख्या में बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। यानी मुस्लिम समाज को इन बेवजह की बहसों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वैक्सीन पर किसी भी प्रकार की अफवाहों को दरकिनार कर मुस्लिम समाज को आगे आकर इस टीकाकरण के साथ खड़े होकर नजीर पेश करने की जरूरत है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

लखनऊ में छात्राओं का वाट्सएप ग्रुप हैककर डर्टी ग्रुप पर डाले नंबर, अश्लील मैसेज भेजकर कर रहे थे परेशान

लखनऊ । एक शातिर युवक ने एक इंटर कॉलेज की छात्राओं का वाट्सएप ग्रुप हैक कर लिया। इसके बाद वाट्सएप ग्रुप के सभी मोबाइल नंबर सोशल मीडिया के डर्टी ग्रुप पर डाल दिया। इसके बाद छात्राओं के पास अभद्र और अश्लीलता भरे फोन आने लगे। छात्रा के पिता की तहरीर पर इंस्पेक्टर गौतमपल्ली आलोक कुमार राय ने आरोपित सौरभ सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर आलोक कुमार राय ने बताया कि करीब 15 दिन दिन पहले सौरभ ने क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज की छात्राओं का वाट्सएप ग्रुप हैक किया था। उसमें करीब 18 से 19 नंबर थे।

आरोप है कि सौरभ ने सारे नंबर डर्टी ग्रुप पर डाल दिए। स्कूल खुलने के बाद वह विद्यालय के गेट के आस आकर खड़ा होता था और छात्राओं का पीछा करते हुए छींटाकशी करता था। बीते दिनों एक छात्रा ने इसकी शिकायत अपने पिता से की। इसके बाद पिता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित सौरभ सिंह पवनपुरी तेलीबाग के देवीखेड़ा का रहने वाला है। वाट्सएप पर अभद्र मैसेज आने पर छात्रा ने जब सौरभ को फोन कर विरोध किया और उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की तो वह उसे धमकाने लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर और सर्विलांस सेल को भी लगाया गया। आरोपित की लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन के आधार पर उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

पटना में लालू-राबड़ी आवास के सुरक्षा गार्ड और सचिवालय पुलिस के बीच भिड़ंत-जमकर बवाल

पटना । राजधानी में गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू यादव व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई। आवास के बाहर भीड़ देख पहुंची सचिवालय थाने की पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इसको लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जिन्हें सचिवालय थाने की पुलिस भीड़ बताकर हटा रही थी वे पार्टी के नेता हैं, जो मीटिंग में भाग लेने आए थे। हालांकि पार्टी नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया है। दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से आयोजित हुई पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि पार्टी जल्द ही विभिन्न मामलों को लेकर मानव श्रृंखला आयोजित करेगी। इसे लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव के अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी की बैठक बुलाई गई है। इसमें बिहार के अलग-अलग जिलों से पार्टी के विधायक व राजद के नेता पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर सुबह से ही 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू-राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ता जुटने लगे थे।

सुरक्षा गार्ड के साथ अंदर जाना चाह रहे थे नेता- सचिवालय थाने की पुलिस का कहना है कि मीटिंग में कुछ लोग अपने सुरक्षा गार्ड के साथ अंदर जाना चाह रहे थे। इसी को लेकर पुलिस की टीम और सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच बहस हो गई। इस बीच मामले को लेकर राजद की तरफ से भी बयान आया है। राजद नेता भोला यादव का कहना है कि जब भी पार्टी के फरियादी मिलने आते हैं तो स्थानीय पुलिस उन्हें बेवजह तंग करती है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है। बिहार पुलिस को कार्यकर्ताओं से मिलने देने में रोक नहीं लगानी चाहिए। लालू-राबड़ी आवास के बाहर आने वाले लोग पार्टी से जुड़े लोग हैं।

टीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, बोले- मांगें पूरी नहीं हुईं तो बैठ जाऊंगा धरने पर

पटना । नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र मांग रहे 94 हजार टीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में बुधवार को उतर आए। उन्होंने सरकार को चेताया कि उनकी मांगें पूरी की जाएं नहीं तो वह खुद भी धरने पर बैठ जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार नियुक्तियों में धांधली कर रही है। सिपाही और दारोगा बहाली के बाद अब शिक्षकों की नियुक्ति में भी मनमानी की जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को धरना दे रहे टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई को चोटें लगी थीं।

इस दौरान काफी देर तक गहमागहमी मची रही। अब मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। गर्दनीबाग धरनास्थल पर बुधवार शाम अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे तेजस्वी ने मौके से ही मुख्य सचिव से फोन पर बात की और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का सबको अधिकार है। तेजस्वी ने कहा कि शिक्षकों की कौन सी सूची तैयार की जा रही है कि अभी तक बहाली की प्रक्रिया बार-बार टल रही है। न मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार हैं और न ही शिक्षा मंत्री। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पटना में दो दिनों की व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया।

तेजस्वी का आरोप- मांगों को किया जा रहा अनसुना- तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार इनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। इसलिए विपक्ष को समर्थन में आना पड़ा है। इंसाफ मिलने तक इन्हें मेरा सहयोग मिलता रहेगा। राजद का नारा है कि बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं।

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- कमेटी की रिपोर्ट का मूल्यांकन किए बिना लाया गया कृषि कानून

चंडीगढ । मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों को बनाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी की मंजूरी लेने के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरटीआइ के जवाब ने इन दावों की पोल खोल दी है। कैप्टन ने कहा कि अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार के इशारों पर झूठा प्रचार कर रही हैं। कैप्टन ने कहा कि योजना आयोग ने सूचना के अधिकार एक्ट के अंतर्गत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कृषि अध्यादेश और जून 2020 में संसद में नए कृषि कानूनों को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल द्वारा मुख्यमंत्रियों पर आधारित कमेटी की रिपोर्ट का मूल्यांकन किए बिना ही लाया गया है। कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकार के इन दावों के उलट शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी शर्मनाक ढंग से इसका प्रचार करती रहीं, ताकि भाजपा के किसान विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। कैप्टन ने कहा कि कृषि कानूनों पर बिना विचार-विमर्श के ही फैसला लिया गया है। अब आरटीआइ के जवाब में भी साबित हो चुका है कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने भी नहीं रखी गई।

उन्होंने कहा कि एक बार रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने से सबको पता चल जाएगा कि कमेटी की मीटिंगों में किसने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि पंजाब तो कमेटी की पहली मीटिंग का हिस्सा भी नहीं था, जबकि दूसरी मीटिंग में मनप्रीत बादल ने भाग लिया, जिसमें सिर्फ कुछ वित्तीय मामलों पर ही विचार हुआ था। तीसरी मीटिंग में सचिव स्तर के अधिकारी ही शामिल हुए। उन्होंने भाजपा, अकाली दल और आप की ओर से ऐसे संवेदनशील मामले में देश को गुमराह करने की आलोचना करते हुए कहा कि इससे बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की तरफ से राहुल गांधी पर उठाए सवालों पर कैप्टन ने कहा कि हरसिमरत को शर्म आनी चाहिए क्योंकि आरटीआइ के जवाब के बाद भी वह लगातार झूठ बोल रही हैं। इसके लिए उन्हें पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरसिमरत की तरफ से किसानों के हितों के प्रति हमदर्दी जताने का नाटक किया जा रहा है, जबकि इससे पहले उन्होंने यह किसान विरोधी कानून थोपने के लिए भाजपा का समर्थन किया था।

सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- जागरूकता से रोकी जा सकती हैं सड़क दुर्घटनाएं, हर दिन होती हैं 65 मौत

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 65 मौतें होती हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब साढे तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के कारकों को खत्म करने के तमाम प्रयास हो रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रदेश भर में जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने परिवहन विभाग की 55.70 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें रोकी जा सकती हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 20 फरवरी तक हर जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमे परिवहन, गृह, स्वास्थ्य विभागों के साथ ही स्कूल कॉलेज शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से

जुड़ी संस्थाएं हैं चाहे लोक निर्माण विभाग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी को सड़क दुर्घटनाओं के कारण चिह्नति करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हाई स्पीड भी सड़क दुर्घटना का कारण बनती है। इसी तरह हाइवे पर अवैध अवरोध भी दुर्घटना का कारण है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना या वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना आदि छोटे-छोटे कैसे कारण हैं, जिनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं से परिवार व समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

गाड़ी चलाने योग्य लाइसेंस देखने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। एक माह तक चलने वाला ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में काफी मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश में हर जिले में जिलाधिकारी इसके नोडल अधिकारी होंगे। स्कूल कॉलेज में जाकर यातायात नियमों की जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। केंद्र सरकार दुर्घटनाएं रोकने के लिए काफी सक्रिय है। उच्चतम न्यायालय भी सड़क दुर्घटनाओं के लिए काफी जागरूक है। अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या उपाय कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि अगले एक माह तक इस कार्यक्रम को करने की जिम्मेदारी जिन जिन विभागों की है, वो पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करें। एक माह बाद 20 फरवरी को कार्यक्रम पूरा होगा तो इसके बाद हम विभागों की समीक्षा करेंगे। जागरूकता अभियान चलाने के बाद नियमों के उल्लंघन करने के बाद मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कर्कवाई की जाए। इस मौके पर सीएम ने सड़क सुरक्षा के लिए शपथ भी दिलाई। इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने भी शिरकत की।

मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से सरकार का कामकाज ठप, जदयू को अब भी भाजपा के पेच सुलझने का इंतजार

पटना । खरमास के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार में अभी बहुत सारे पेच नजर आ रहे हैं। जदयू की ओर से सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। भाजपा की कवायद भी जारी है, मगर निष्कर्ष पर पहुंचने में अभी कई मोड़ से गुजरना बाकी है। जदयू को भाजपा के इस पेच के सुलझने का इंतजार है। किंतु मंत्रिमंडल विस्तार में देर होने का साइड इफेक्ट सरकार के कामकाज पर दिख रहा है।

पांच महीने से सरकार के कार्य को रफ्तार नहीं- कई विभागों के कामकाज में व्यवधान आ रहा है। संवैधानिक नियमों के तहत बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी मात्र 14 मंत्री हैं, जबकि विभागों की कुल संख्या 44 है। जाहिर है, एक-एक मंत्री के पास कई-कई विभाग हैं, जिसके चलते वे अपने विभागों में बैठ भी नहीं पा रहे हैं। काम की बात तो दूर है। कुछ विभाग तो ऐसे भी हैं, जहां अभी तक मंत्री के कदम भी नहीं पड़े हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के टलने के कारण पिछले करीब पांच महीने से सरकार के कार्यों को रफ्तार नहीं मिल सकी है। विधानसभा चुनाव के दो महीने पहले से ही आचार संहिता के कारण काम प्रभावित रहे। अब नई सरकार के गठन के भी दो महीने से यादा हो गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार बार-बार टल रहा है। पेंच भाजपा की तरफ से है। उसने अभी तक संभावित मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री को नहीं सौंपी है। जदयू की ओर से नीतीश कुमार ने कई बार साफ कर दिया है कि सहयोगी दल की तरफ से जब भी सूची आएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा।

19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही संकेत दे दिया है कि विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। ऐसे में सदन में एक ही मंत्री को कई-कई विभागों से संबंधित सवालों को जवाब देना होगा।

यह असंवैधानिक तो नहीं होगा पर इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठना लाजिमी है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर भी लिया जाएगा तो भी दूसरी समस्या आएगी। नए मंत्रियों के पास सदन की तैयारी के लिए बहुत कम समय होगा।

राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र, विश्वामित्र आश्रम में होगी बैठक

अयोध्या । संपूर्ण रामजन्मभूमि परिसर के विकास की कार्ययोजना को भी अंतिम रूप देने के लिए आज से शुरू हो रही दो दिवसीय बैठक के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गए हैं। वह राम जन्मभूमि परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आज की पहली बैठक कार्यदाई संस्था एलएंडटी और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों के साथ राम जन्मभूमि के परिसर विश्वामित्र आश्रम में होगी। वहीं दूसरी बैठक दोपहर के बाद बाद सर्किट हाउस में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और टाटा कंसल्टेंसी और एलएनटी के इंजीनियरों के साथ होगी। बैठक में शामिल होने के लिए आर्किटेक्ट सोमपुरा भी पहुंचे हैं। बैठक में इंजीनियर पुरानी पद्धति से मंदिर निर्माण के लिए नीव की डिजाइन पेश करेंगे। वहीं इन दिनों राम मंदिर निर्माण के लिए गर्भगृह के आसपास से मिट्टी हटाई जा रही है। बैठक चार चरण में होगी, जिसमें पहले चरण की बैठक में राम ट्रस्ट व निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे।

राम मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक में रामजन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की नींव के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगाये जाने के साथ संपूर्ण रामजन्मभूमि परिसर के विकास की कार्ययोजना को भी अंतिम रूप दिया जाना है। हालांकि राम मंदिर की नींव की खोदाई 15 जनवरी से ही शुरू हो गयी है और नींव के प्रारूप पर भले ही निर्माण समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी, पर उसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

नींव का यह प्रारूप पाषाण के बड़े भवनों की पारंपरिक निर्माण शैली के अनुरूप कांटीन्युअस राफ्ट स्टोन प्रणाली के अंतर्गत है और यह शैली अपनाने के निष्कर्ष पर आईआईटी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, गुवहाटी, अहमदाबाद सहित नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ तथा मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि करीब माह भर के गंभीर मंथन के बाद पहुंचे हैं।

15 जनवरी से नींव की खोदाई शुरू होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नींव निर्माण में कोई दिक्कत नहीं रह गयी है और बैठक के बाद निर्माण की गति में और तीव्रता लाये जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल, बैठक में हिस्सा लेने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष एवं अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र बुधवार की शाम अयोध्या पहुंच गये।

उन्होंने सर्किट हाउस में कुछ पल विश्राम के बाद बैठक शुरू होने की पूर्व संध्या पर रामनगरी स्थित बजरंगबली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी पहुंच बजरंगबली का दर्शन-पूजन किया।

बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को ही देर रात रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है।

बैठक को ही ध्यान में रख कर गत कई दिनों से अयोध्या से बाहर गये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय मंगलवार को ही वापस अयोध्या लौट आए। बैठक में प्रस्तावित मंदिर के मुख्य शिल्पी सीके सोमपुरा के प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र आशीष एवं निखिल सोमपुरा सहित मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था एलएंडटी तथा टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स के प्रतिनिधि सहित कई अन्य शीर्ष वास्तुविद शामिल होंगे।

खोज लिया गया नींव की समस्या का समाधान मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू होने की पूर्व संध्या पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने स्पष्ट किया कि मंदिर की नींव के लिए देश के नौ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और उन्होंने नींव की समस्या का समाधान खोज भी लिया है और इसी के तहत 15 जनवरी से नींव का काम शुरू हो चुका है।

समस्तीपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार देने की कवायद, इन बिंदुओं पर विशेष रूप से रखना है ध्यान

समस्तीपुर । पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पूरक पोषाहार की गुणवत्ता का अब पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से सभी रायों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिया गया है। पूरक पोषाहार संबंधित निर्देशों में कहा गया है कि अब लाभार्थी को दिए जाने वाले पूरक पोषाहार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दिए गए मापदंडों को पूरा करते हों जिसके तहत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार देना सुनिश्चित किया जाना है।

निर्देश के मुताबिक लाभुक को दिए जाने वाले टेक-होम राशन को पहले भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए आंगनबाड़ी सेवा से जुड़े अधिकारियों जैसे सीडीपीओ व सुपरवाइजर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार की स्टॉक की प्राप्ति के बाद सैंपलों की जांच जरूर करानी है। गर्म पके हुए भोजन दिए जाने की स्थिति में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि खाना उचित तरीके से तैयार किया गया हो। इसमें रसोई घर की सही तरीके से सफाई व साफ पेयजल का ध्यान रखना भी शामिल है। रायों में निर्देश दिया गया है कि पूरक पोषहार की आपूर्ति श्रृंखला की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाये तथा किसी प्रकार की आपूर्ति में बाधा नहीं हो। पंजीकरण व भंडारण प्रक्रियाओं के तहत पोषाहार संबंधी मानकों का पालन हो रहा है, इसे भी सुनिश्चित करना है।

पोषण की स्थिति का जायजा लेने व नियमकों का पालन करवाने के लिए जिला स्तर पर डीएम नोडल अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी अनुश्रवण व निगरानी के लिए तैयार जिला पोषण समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला पोषण समिति द्वारा नियुक्त किये गये पोषण विशेषज्ञ प्रमाणित होंगे।

आइसीडीएस व पोषण कार्यक्रमों के संचालन के लिए समेकित बाल विकास पदाधिकारी डीएम के निगरानी में काम करेंगे। सीडीपीओ जिला स्तर पर पोषण की मदद से लाभार्थियों विशेष कर कुपोषित बचों की सेहत में हुए परिवर्तन की जांच करेंगे।

अजीत सिंह हत्याकांड : उठेगा सभी रहस्यों से पर्दा, एक और शूटर समेत तीन दबोचे गए

लखनऊ । अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ पुलिस ने हरियाणा से हत्या करने आए एक और शूटर को गिरफ्तार किया है। शूटर का नाम मुस्तफा बताया जा रहा है। इस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है। पुलिस ने हमलावरों की मदद करने आजमगढ़ से आए मददगार अंकुर और बंधन को भी मुंबई से पकड़ा है। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर आज (गुरुवार) अजीत हत्याकांड से जुड़े सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।

गौरतलब है की हत्याकांड की जड़ अब मुन्ना बजरंगी के हत्यारोपित सुनील राठी से जुड़ रही है। गैंगवार में जिस शूटर को गोली लगी थी, उसकी लखनऊ पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के मुताबिक घायल शूटर अलीगढ़ निवासी राजेश तोमर है। राजेश कुख्यात सुनील राठी का करीबी है। राजधानी पुलिस ने आंबेडकरनगर में बलुआ चंदौली निवासी संदीप सिंह उर्फ बाबा समेत दो लोगों को दबोचा है। संदीप ने राजेश तोमर के साथ मिलकर अजीत पर गोलियां बरसाई

थीं। संदीप सदर कोतवाली उकरा गांव निवासी अपने परिचित देवेंद्र सिंह के घर पर छिपा था। पुलिस देवेंद्र और उसके साथी संजय सिंह से पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि संदीप ने राजेश तोमर व अन्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उधर, पुलिस आयुक्त ने बताया कि राजेश तोमर बागपत में जून 2020 में हुई परमवीर तुगाना की हत्या में वांछित है। राजेश पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है और बागपत पुलिस राजेश की तलाश कर रही है।

सुनील राठी ने जेल में की थी मुन्ना बजरंगी की हत्या - 9 जुलाई 2018 को सुनील राठी ने बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्तमान में सुनील तिहाड़ जेल में बंद है। खास बात यह है कि अजीत के हत्यारोपित को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो तिहाड़ जेल में ही बंद है।

वहीं अजीत हत्याकांड में नामजद आरोपित कुंटू सिंह और अखंड को आजमगढ़ से बी वारंट पर बुधवार को लखनऊ सीजेएम तृतीय के यहां पेश किया गया था। हालांकि इस दौरान लखनऊ पुलिस की ओर से पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोई अर्जी नहीं डाली गई। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के मुताबिक दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेशकर वापस ले जाने के आदेश थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कुंटू और अखंड को पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) पर लिया जाएगा। लखनऊ पुलिस दोनों की पीसीआर के लिए न्यायालय में अर्जी देगी। पीसीआर पर लेने के बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी। उधर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कुंटू और अखंड को आजमगढ़ से लखनऊ लाया गया था। कोर्ट परिसर में कुंटू ने मीडियाकर्मियों को दिए बयान में कहा कि उसका पूर्व सांसद धनंजय सिंह से कोई संबंध नहीं है। अजीत सिंह की हत्या में कुंटू के शामिल होने के सवाल पर उसने बताया कि वह इस बारे में कोर्ट में अपना जवाब देगा।

बिहार : लेट लतीफी व काम टालने के लिए बदनाम हैं बेचारे बाबू, आइएएस अधिकारी भी कहां हैं पीछे

पटना । सरकारी कामकाज में बाबू लोगों की लेट लतीफी और काम टालने की नई-नई तरकीब के इतने किस्से हैं कि लोग इनकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन बिहार की चर्चा करें, बानगी देखें तो कह उठेंगे- बाबू तो बेचारे बदनाम हैं, काम टालने के मामले में शीर्ष पर बैठे आइएएस अधिकारी कम से कम इस मोर्चे पर उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। बेशक उनके बीच तेज रफ्तार से काम करने वाले अधिकारी भी हैं। फिर भी उनकी संख्या कम नहीं है, जो टलते रहने की हद तक किसी काम को टाल सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके विचार के लिए आया विषय अंतत- किसके हित से जुड़ा है। यहां तक कि वे अपनी भलाई के मामले में भी जल्दबाजी नहीं करते। रिमाइंडर का इंतजार करते हैं। बस, वही तारीख पर तारीख जैसा मामला समझ लीजिए।

13 डीएम सहित 20 अफसरों को पत्र- राज्य सरकार के अधिकारियों का लेखा जोखा सामान्य प्रशासन विभाग के पास रहता है। इसे आप कारपोरेट के लिहाज से एचआर डिपार्टमेंट कह सकते हैं। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 जनवरी को एक पत्र जारी किया। यह बिहार में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों के नाम है। ये सब 2011, 2012 एवं 2013 बैच के अधिकारी हैं। इनमें से 13

फिलहाल विभिन्न जिलों में डीएम के पद पर तैनात हैं। बाकी सचिवालय में हैं या जिलों में किसी न किसी महत्वपूर्ण पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हवाले से पत्र जारी किया गया है। यह पत्र दरअसल रिमाइंडर है, जिसे सरकारी भाषा में स्मार पत्र कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को पत्र दिया गया है, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण में जाना है। यह प्रशिक्षण इस साल 22 फरवरी से 19 मार्च तक है। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अधिकारियों को संबंधित वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना है। 19 जनवरी के पत्र में अधिकारियों को याद दिलाया गया है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 जनवरी है। जाहिर है, इस तारीख तक अधिकारी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जबकि यह अनिवार्य प्रशिक्षण है।

डेढ़ महीने से चल रही है प्रक्रिया- पहली बार भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने तीन दिसम्बर 2020 को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को इसके बारे में पत्र लिखा। इस पत्र की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 दिसम्बर 2020 को एक पत्र इन अधिकारियों को अलग से भेजा। 28 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से एक सप्ताह पहले इन अधिकारियों को याद दिलाने के लिए 19 जनवरी को पत्र लिखना पड़ा कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाएंगे।

जनहित के मामले में भी यही रूख- प्रशिक्षण किसी अधिकारी के कैरियर का विषय है। पिछड़ गए तो निजी नुकसान होगा। लेकिन, राज्य हित के मामलों में भी ऐसी ही सुस्ती नजर आती है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को 31 दिसम्बर 2020 को एक पत्र लिखा। पत्र में आग्रह किया गया कि सभी विभाग चालू वित्त वर्ष के सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट के लिए अपने विभाग का प्रस्ताव भेज दें। प्रस्ताव भेजने की आखिरी तारीख आठ जनवरी तय की गई। वित्त विभाग ने आठ के बदले 18 जनवरी तक विभागों के प्रस्ताव का इंतजार किया। सभी विभागों के प्रस्ताव नहीं मिले। 18 जनवरी को सिद्धार्थ ने एक और पत्र जारी किया। इसमें प्रस्ताव भेजने की आखिरी तारीख 22 जनवरी तक इस हिदायत के साथ दी गई है कि उसके बाद अगर उनके प्रस्ताव मिले तो उसे सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट में शामिल नहीं किया जाएगा।

राज्य को क्या नुकसान होगा- विधानमंडल का सत्र 19 फरवरी से आयोजित है। इसमें सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पारित होगा। पूर्ण बजट में निर्धारित राशि से अधिक किसी विभाग में खर्च है तो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट से उसकी भरपाई की जाती है। इतना ही नहीं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अगर राज्य के हिस्से से दी जाने वाली राशि कम पड़ रही है तो उसकी भी भरपाई होगी। सिद्धार्थ के पत्र में विभागों को सावधान किया गया था-कहीं ऐसा न हो कि राज्य का हिस्सा न मिलने की हालत में केंद्र की राशि के सरेंडर करने की नौबत आ जाए।

ठेकेदार नितेश सिंह बबलू हत्याकांड में वांछित गिरधारी की आज जनवरी को हो सकती है पेशी

वाराणसी । तहसील में ठेकेदार नितेश सिंह बबलू की हुई हत्या में वांछित गिरधारी विश्वकर्मा की न्यायालय में शुक्रवार को पेशी सम्भव है। उसे तिहाड़ जेल से लाने के लिए अदालत ने वारंट बी जारी किया है। शिवपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि चोलापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डाक्टर उर्फ कन्हैया वर्ष 2019 में हुए नितेश बब्लू हत्याकांड मामले में वांछित है।

दिल्ली पुलिस ने 12 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था जहां से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल से लाने के लिए उसके विरुद्ध वारंट बी जारी करने की अपील की। अदालत ने इस अपील को मंजूर करते हुए गिरधारी विश्वकर्मा के खिलाफ वारंट बी जारी किया है। उसे 22 जनवरी को तलब किया गया है। उधर, लखनऊ पुलिस भी मऊ निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख की हत्या में गिरधारी को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रशाद योजनांतर्गत अमरकंटक में 49.98 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास

नर्मदा को स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सभी का दायित्व

नर्मदा के आशीर्वाद से मध्यप्रदेश में आती है सुख-समृद्धि

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पवित्र नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा के आशीर्वाद से प्रदेश में सुख-समृद्धि आती है। पवित्र नर्मदा नदी के उद्गम-स्थल अमरकंटक को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

श्री चौहान गुरुवार को अनूपपुर जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजनांतर्गत धार्मिक पर्यटन क्षेत्र अमरकंटक में 49.98 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं अमरकंटक क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह, क्षेत्रीय सांसद हिमाद्रि सिंह सहित जन-प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के उदगम-स्थल में गंदा पानी और मैला न मिले इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उद्गम स्थल को स्वच्छ, सुंदर और पवित्र बनाए रखने के लिए जनमानस के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पवित्र अमरकंटक नगरी साधु-संत एवं ऋषि मुनियों की तप-स्थली रही है। इसे पवित्र बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अमरकंटक क्षेत्र के नागरिक एवं संत समाज इस दिशा में सोचें कि पवित्र नर्मदा नदी में किसी प्रकार गंदगी न पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा जल ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य आगामी 6 माह में पूरा कर नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में पौधरोपण किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि अमरकंटक में पक्के निर्माण कार्यों एवं सीमेण्ट-कांक्रीट के कार्यों को प्रतिबंधित किया जाये। उन्होंने कहा कि अमरकंटक क्षेत्र के पर्यावरण को वैज्ञानिक ढंग से संतुलित किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि नर्मदा नदी का संरक्षण और संवर्धन हो, जिससे नर्मदा का जल पुनः कल-कल बहे। उन्होंने कहा कि अमरकंटक क्षेत्र के गायत्री और सावित्री सरोवरों से गाद निकालने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजनांतर्गत अमरकंटक में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे अमरकंटक का स्वरूप बदलेगा और पर्यटक आकर्षित होंगे। अमरकंटक क्षेत्र के जंगल में कुटियों के निर्माण के साथ ध्यानकुटी भी बनाई जाएगी।

शिवराज ने की नर्मदा की पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री चौहान एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अमरकंटक में नर्मदा उद्गम मंदिर में मां नर्मदा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। श्री चौहान ने मां नर्मदा से प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, सांसद हिमाद्रि सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

नर्मदा को गंदगी से बचाने के होंगे प्रयास : पटेल

केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नर्मदा भक्त के रूप में अमरकंटक के विकास के लिए नर्मदा ने मुझे निमित्त बनाया है। नर्मदा के लिए मुझे कुछ अच्छा करने का अवसर मिला है, जिसे वे अपना भाग्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा की सुंदरता के अलावा स्वच्छता पर भी ध्यान देने की आवश्यता है। अमरकंटक क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्षेत्र में व्यवसायिक भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध होना चाहिए तथा गंदगी नर्मदा के आंचल में न जाए, इसके प्रयास करने होंगे।

रामगमन पथ निर्माण के प्रयास किए जाएं : उषा ठाकुर

संस्कृति मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि रामगमन पथ के निर्माण के प्रयास किए जाएं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नर्मदा क्षेत्र साधु-संतों और महात्माओं का पवित्र क्षेत्र रहा है। हम नर्मदा पुत्र है, हमारे जनजातीय समाज के लोगों ने आदिकाल से साधु-संतों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि आगामी दिवसों में नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। समारोह को क्षेत्रीय सांसद हिमाद्रि सिंह ने भी संबोधित किया।

शिवराज सिंह ने हितग्राहियों को वितरित किए हित लाभ

मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ने मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक योजना के तहत 8.01 करोड़ लागत के कार्यों का लोकार्पण एवं 24.92 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या-पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य और अनूसचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रूपमती सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पनाडिया, विधायक जयसिंह मरावी, विधायक मनीषा सिंह, कमिश्नर शहडोल संभाग नरेश पाल सहित अन्य जन-प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को अपने इंदौर प्रवास के दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के जानकी नगर स्थित निवास पर पहुंचे। मंत्री सिलावट ने उनका स्वागत किया और इंदौर में विद्युत विभाग की विभिन्न परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : तोमर

भोपाल (एजेंसी)।

प्रदेश में वर्षों पहले किए गए सौलर पावर के एग्रीमेंट के आधार पर अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। इसमें लगने वाले फिक्स चार्ज कम करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन का प्रयास है कि उत्पादन के क्षेत्र में नई यूनिट लाने की योजना है। जल विद्युतगृह पुराने हैं, उनकी मरम्मत कर के 10 साल और चलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की उत्पादन क्षमता 5400 मेगावॉट की है, लेकिन 3200 मैगावॉट का उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को इंदौर में कही।

छह लाख आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी, 300 करोड़ बचेंगे

उन्होंने बताया कि विद्युत कंपनियों के कार्य में सुधार करने के लिए समय पर मैंटेनेंस, शिकायत मिलने पर समय सीमा में सुधार करने का कार्य किया गया है। ट्रिपिंग कम करने के साथ ही जनरेशन खर्च भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंदौर में मीडीया से चर्चा करते हुए बताया कि पुराने एग्रीमेंटों के आधार पर अधिक राशि के भुगतान के मामलों की समीक्षा की जा रही है। वहीं मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर्मचारी ठेकेदार कंपनियों द्वारा किए गए पीएफ घोटाले के सवाल पर उन्होंने कहा कि गलत का बचाव नहीं किया जाएगा।

श्री तोमर ने 100 रुपए में 100 यूनिट योजना से बाहर किए जा रहे छह लाख उपभोक्ताओं पर कहा कि इस योजना में सब्सिडी के रूप में 467 रुपए का भुगतान शासन कर रहा है। सक्षम और संपन्न परिवार भी इसका लाभ पा रहे हैं। इसमें डाक्टर इंजीनियर सहित उद्योगपति भी शामिल हैं। छह लाख आयकरदाता उपभोक्ताओं को हटाने से प्रति वर्ष 300 करोड़ तक की राशि बचेगी। इस योजना में जल्दी ही गिव अप का आप्शन भी मिलेगा। कोई भी अपनी स्वेच्छा से बिजली की सब्सिडी को छोड़ सकेगा। श्री तोमर ने बताया कि वे बिजली कंपनी स्टोरों में होने वाली खरीदी को डिमांड बेस्ड बना रहे हैं। इससे आवश्यकता से अधिक खरीदी नहीं होगी। वाणिज्यिक घाटे को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने बिजली के आंकलित बिलों पर रोक लगाने और अधिक राशि के बिलों में सुधार करने की बात भी कही।

कमलनाथ को कोषाध्यक्ष और पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की तैयारी

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भले ही इस बात का दावा कर चुके हों कि वे मध्यप्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान लगभग यह तय कर चुका है कि कमलनाथ को पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में पदस्थ किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव के अलावा कुछ राज्यों का प्रभार और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा जा सकता है। इन दोनों ही नेताओं का कद निश्चित तौर पर बढ़ेगा।

कमलनाथ होंगे दस जनपथ में सबसे पावर फूल

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेहद खास अहमद पटेल के निधन के बाद से ही उनके स्थान को भरने की कवायद शुरू हो गई थी। उनके स्थान पर गांधी परिवार अपने किसी नजदीकी नेता को जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, लेकिन अब कांग्रेस में इस स्तर का कोई भी नेता शेष नहीं है। ऐसे में इंदिरा गांधी के समय से गांधी परिवार के सबसे नजदीक रहे कमलनाथ ही एकमात्र विकल्प हैं। पिछली बैठकों में हुई चर्चा के अनुसार कई आला कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सहमति जाहिर की है। गांधी परिवार भी चाहता है कि मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल की जगह अब कमलनाथ जिम्मेदारी लें। हालांकि अब तक कमलनाथ ने इसकी सहमति नहीं दी है। फिर भी कांग्रेस हाईकमान लगभग यह तय कर चुका है कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष पद पर कमलनाथ को पदस्थ किया जाएगा। उनके कोषाध्यक्ष बनने से पहले मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कमलनाथ के विश्वसनीय किसी नेता को पदस्थ किया जाएगा।

कमलनाथ ही क्यों

राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पास अनुभवी नेताओं की बेहद कमी है। इसके अलावा गांधी परिवार के विश्वसनीय लोगों में कमलनाथ ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ बेहतर काम किया है। उनकी निष्ठा कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति अटूट है। इसके अलावा उनमें पार्टी मैनेजमेंट से लेकर चुनाव मैनेजमेंट तक के बेहतर गुण हैं। जिसकी वजह से कमलनाथ को अब कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है।

सचिन पायलट होंगे कांग्रेस का नया युवा चेहरा

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की भीड़ को खींचने वाला कोई चेहरा मौजूद नहीं है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कमी को पूरा करते थे, लेकिन बीते मार्च माह में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ले ली, जिसकी वजह से एक बड़ा स्थान खाली हो गया। कांग्रेस आलाकमान इस खाली स्थान को भरा चाहता है और सचिन पायलट जैसे प्रतिभावान नेता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, मीडिया प्रभारी और कुछ राज्यों का प्रभारी बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पर इससे पायलेट का कद पार्टी में बढ़ेगा। यह भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को देश भर में सभाएं, दौरे करने की आजादी होगी और संगठन में युवाओं की फौज खड़े करने की योजना तैयार करने को कहा गया है।

प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिल्ली में बन रहे मध्यप्रदेश भवन का अवलोकन किया

भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान दिल्ली में बन रहे मध्यप्रदेश भवन के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान प्रमुख सचिव विधानसभा एपी सिंह सहित मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रोटेम स्पीकर श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के जनप्रतिनिधियों अधिकारी-कर्मचारियों और नागरिकों की सुविधा के लिए इस भवन का निर्माण कराया जा रहा है । उन्होंने बताया कि उक्त भवन के निर्माण के लिए पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के प्रयासों से भवन के लिए ज़मीन का आवंटन हुआ था। सर्वसुविधा युक्त यह भवन मध्यप्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, यही अपेक्षा है।

कोविड-19 के उपचार दर रिसेप्शन पर प्रदर्शित करें : कुर्रे

भोपाल (एजेंसी)। मप्र के स्वास्थ्य आयुक्त ने प्रदेश के सभी क्लीनिक और नर्सिंग होम को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित की गई दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के के निर्देश दिए हैं।

संचालक स्वास्थ्य, सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो वसंत कुर्रे ने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा नवंबर 2020 में कोविड-19 की निर्धारित उपचार दरों को क्लीनिक और नर्सिंग होम में रिसेप्शन काउन्टर पर प्रदर्शित करने के संबंध में पारित आदेश के अनुक्रम में निर्देश जारी किए गए हैं। मरीजों और परिजनों द्वारा दरों की मांग करने पर उन्हें भी उपचार की दरें उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री कुर्रे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्लीनिक्स इस्टाविलिशमेंट और नर्सिंग होम संबंधी रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन नियम के प्रावधानों के तहत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस मामले में यह भी स्पष्ट किया है कि क्लीनिक एवं नर्सिंग होम सीएमएचओं को कोविड-19 की निर्धारित दरों की भेजी गई सूची में दर्शाई दरों से 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उपचार की तय दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे जिला प्रशासन और हाईकोर्ट को आवश्यक कार्यवाही के लिए भी भेजा जाएगा।

मेपकास्ट और आईआईटी के बीच हुआ एमओयू

भोपाल (एजेंसी)। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकास्ट) भोपाल एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), इन्दौर के बीच खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी के क्षेत्र में हुए सहमति-पत्र के अंतर्गत दोनों संस्थान शोध, संचार, शिक्षा और विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करेंगे।

यह जानकारी परिषद् के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर के दौरान दी। मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकास्ट) भोपाल के तकनीकी सहयोग से इंदौर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में मोबाइल तारामंडल की स्थापना प्रस्तावित है। मोबाइल तारामंडल की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों में खगोल विज्ञान में रूचि पैदा करना है। डॉ. कोठारी ने बताया कि खगोल विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों, विंटर स्कूल, संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जायेगा।

खगोल विज्ञान में शोध संचार-शिक्षा और विकास में सहयोगी बनेंगे

उज्जैन तारामंडल के कार्यक्रमों में आईआईटी के विद्यार्थियों को सहभागी बनाया जायेगा। तारामंडल आधारित ब्रह्मांड संबंधी कार्यक्रमों के निर्माण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा। महानिदेशक ने बताया कि दोनों संस्थान खगोल भौतिकी विशेष रूप से ऑप्टीकल एस्ट्रोनॉमी में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में परस्पर सहयोग करेंगे। इंदौर स्थित आईआईटी के जरिये डोंगला स्थित वराहमिहिर वेधशाला के खगोलीय प्रेक्षणों को नियंत्रित किया जाएगा।

इसी प्रकार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा विश्लेषण डोम का ऑटोमेशन और ब्रमांडीय पिंडों की खगोलीय फोटोग्रॉफी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग किया जायेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर के निदेशक डॉ. एनके जैन ने अपनी संस्था की ओर से हस्ताक्षर किए।

पत्रकारों को भी लगवाया जाए कोरोना का नि:शुल्क टीका

भोपाल (एजेंसी)। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का निःशुल्क टीका लगवाने का अनुरोध किया है। श्री कमलनाथ ने अपने पत्र में कोरोना महामारी से निपटने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित करने में अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है।

कमलनाथ ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किया अनुरोध

उन्होंने कोरोना काल में संक्रमण से रोगियों को मुक्त कराने में योगदान देने वाले चिकित्सकों और उनके सहयोगियों को भी बधाई दी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इसके साथ ही एक वर्ग ऐसा है जिसने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी संक्रमण की रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। यह वर्ग मीडिया से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार साथियों और उनके संस्थान में कार्यरत लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अनवरत काम किया और संक्रमण की रोकथाम में अहम योगदान दिया। इन लोगों ने कोरोना से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के प्रति भी संवेदनशीलता और उनके जज्बे का सम्मान किया जाना चाहिए। श्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि कोरोना टीकाकरण अभियान में जिस तरह अन्य लोगों को जोड़ा गया है, उसी प्रकार मीडियाकर्मियों को भी प्राथमिकता प्रदान कर उनका निःशुल्क टीकाकरण किया जाए।

ग्राम करताना में राष्ट्रीय शूटिंग बॉल स्पर्धा के समापन समारोह में युवाओं से किया खेलों में सक्रिय होने का आह्वान

हरदा अब खेलों में भी बनेगा नंबर वन : पटेल

हरदा, (एजेंसी)। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के युवाओं से खेल स्पर्धाओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने और जिले का नाम रोशन करने का आह्वान किया है। ग्राम करताना में राष्ट्रीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के फायनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिले में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

ग्राम करताना में राष्ट्रीय शूटिंग बॉल स्पर्धा का यह तीसरा आयोजन है। स्पर्धा के फायनल में पहुंची राजस्थान और उत्तर प्रदेश की टीम में रोचक मुकाबला हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने जीत हासिल की। स्पर्धा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा हर मामले में नंबर वन है, इसे खेलों में भी नंबर वन बनाना है। कृषि मंत्री पटेल ने हरदा में खेल के मैदानों का विकास कर अभ्यास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। मंत्री पटेल ने कहा कि वह बॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, खेल के कारण ही उन्हें इंदौर जाकर पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि खेल जीवन के लिए आवश्यक है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में विधायक आशीष शर्मा, किसान नेता और खिरकिया जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुदीप पटेल डूडी, जिला भाजपा अध्यक्ष अमरसिंह मीणा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रतिभागी टीम के खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनसे खेल भावना के अनुरूप प्रदर्शन का आह्वान किया।

प्रतिभागियों को 5-5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा : कृषि मंत्री कमल पटेल घोड़ा घोड़ी चाल प्रतियोगिता में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस स्पर्धा में अनेक घुड़सवारों ने हिस्सा लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मंत्री री पटेल ने स्पर्धा के आयोजकों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों को पांच पांच हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के धौलपुर खुर्द तहसील टिमरनी में चल रही श्रीराम कथा में आध्यात्मिक सत्संग-संगीत के साथ कथा में भगवती स्वरूपा कन्याओं का चरण पूजन करने के बाद राघवेंद्र जी महाराज अयोध्या धाम के मुखारविंद से चल रही कथा का श्रवण कर गादी पीठ की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर श्री पटेल ने उपस्थित श्रद्धालुओं से अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण में गिलहरी सेवा के रूप में सहयोग करने का आह्वान किया।

नारी के सम्मान और बेटियों को शिक्षित करने से ही भारत माता को विश्वगुरु बनाया जा सकता है : पटेल

कृषि मंत्री कमल पटेल ने साइकिल चलाकर सम्मान अभियान का समापन किया। आपने कहा कि देश को आत्म निर्भर बनाने में बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहे जिसके लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। बेटियों की सुरक्षा, मातृशक्ति का सम्मान बढ़े जिससे एक अच्छा वातावरण बने , मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मातृशक्ति से दुनियां का निर्माण हुआ है, भारत माता को विश्व का सिरमौर बनाया जा सके, विश्वगुरु बनाया जा सके, उसके लिए बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा प्राथमिक रूप लिया जाना चाहिए। आपने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां नारियों का न सिर्फ सम्मान किया जाता है बल्कि पूजा भी जाता है। इस अभियान में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा भी कई आयोजन किए गए हैं, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी नारी सशक्तिकरण को प्रदेश में कई जन जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। देश आत्मनिर्भर बनाए जाने वाले इस अभियान में सभी मीडिया और प्रेस के साथियों ने भी भरपूर उत्साह और जागरूकता के साथ योगदान दिया है। मंत्री श्री पटेल ने मीडिया प्रेस सहित तमाम समाज सेवी संगठनों का आभार व्यक्त किया है।

नेहा कक्कड़

ने पति रोहनप्रीत सिंह को दी धमकी, कहा- अपनी एक्स को कॉल किया तो...

सिंगर नेहा कक्कड़ का सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह पति रोहनप्रीत सिंह को धमकी देती नजर आ रही हैं कि अगर उन्होंने अपनी एक्स को कॉल किया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि, यह एक मजेदार वीडियो है, जिसमें नेहा कक्कड़ पति रोहनप्रीत संग मजाक करती नजर आ रही हैं।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोहनप्रीत सिंह 'एक्स-कॉलिंग' गाने पर एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद नेहा कक्कड़ उन्हें धमकी देती हैं कि वह अपनी एक्स को कॉल न करें, क्योंकि उसने किसी और के लिए रोहनप्रीत को धोखा दिया है। नेहा कक्कड़ ने कैप्शन में लिखा, एक्स कॉलिंग अच्छा कर तू कॉल फिर बताती हूं, हा हा हा, रोहनप्रीत सिंह, मुझे इस गाने से प्यार है।इस पर रोहनप्रीत सिंह ने कॉमेंट करते हुए लिखा, ओ कोई नी कोई नी कोई नी गुस्सा नी करना। आपको इस गाने से प्यार है और मुझे आपसे प्यार है

मालूम हो कि दोनों ने साल 2020, अक्टूबर में शादी रचाई थी। तभी से दोनों अपने म्यूजिक वीडियोज और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं।

रोहनप्रीत ने नेहा संग बताई थी अपनी पहली लव स्टोरी

नेहा और रोहनप्रीत सिंह ने पिछले साल धूमधाम से शादी की थी। दोनों की शादी की फोटोज और वीडियो जमकर वायरल हुए थे। हाल ही में 'इंडियन आइडल' शो के मंच पर रोहनप्रीत सिंह ने नेहा कक्कड़ और अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। रोहनप्रीत सिंह ने बताया कि कैसे उन्हें और नेहा को पहली नजर में ही एक-दूसरे से प्यार हो गया था।

रोहनप्रीत सिंह जब लव स्टोरी सुना रहे थे तो नेहा कक्कड़ बेहद भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल, 'इंडियन आइडल' की एक प्रतिभागी ने दोनों से पूछा था कि आखिर आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। इस पर जवाब देते हुए रोहनप्रीत ने कहा कि आप यह कह सकती हैं कि आखिर मेरी लाइफ चेंज कैसे हुई।

रोहनप्रीत सिंह ने बताया, मैं एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी बांध रहा था और इनके मैनेजमेंट की ओर से कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि नेहा कक्कड़ का नया गाना आ रहा है। क्या आप उसमें उनके को-स्टार के तौर पर काम करेंगे? इस पर मैंने कहा कि क्या यह पूछने की बात है। मैं जब वहां गया और एंट्री कर रह था तो नेहा ने मुझे मुड़कर देखा। वह मेरा दिन था और आज आपके सामने बैठा हूं। आप यह कह सकते हैं कि वह मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मैं तो यह कहूंगा कि यह जिनके भी करीब रहती हैं, भगवान उनकी जल्दी सुन लेता है। इन्होंने वह गाना तो लिखा ही, उसके साथ ही इन्होंने मेरी किस्मत भी लिख दी।

आलिया भट्ट

को काम के प्रेशर के चलते हुआ टेंशन, हॉस्पिटल में होना पड़ा भर्ती

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने काम को लेकर बहुत बिजी चल रही हैं। वह एक के बाद प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ा है। इन दिनों आलिया डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए शूटिंग कर रही हैं, लेकिन काम के प्रेशर के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे में उन्हें 17 जनवरी को सर एच एन रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा।

पीपिंग मून के अनुसार, आलिया उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गईं। ठीक होने के बाद वह सोमवार सुबह यानी 18 जवनरी की सुबह फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट पर पहुंच गईं और शूटिंग शुरू कर दी है। हालांकि, आलिया के अस्पताल में एडमिट होने को लेकर फिल्म की टीम की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

बताते चलें कि आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी विवादों आ गई है। गंगूबाई के बेटे का कहना है कि जैदी की किताब के कुछ हिस्से बदनाम करने वाले हैं, जिससे उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए, वह चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग को रोक दिया जाए। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी के परिवार ने इस फिल्म को लेकर केस भी दर्ज कराया है।आलिया भट्ट की यह फिल्म पहले 11 सितंबर 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग समय पर पूरी नहीं हो सकी। अब चर्चा है कि मेकर्स इस फिल्म को दिवाली पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। इस फिल्म के अलावा आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी की ब्रह्मस्त्र और बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR' में भी नजर आएंगी।

शादी के बाद हनीमून के लिए पति जैद दरबार संग उदयपुर पहुंचीं गौहर खान, तस्वीरों में देखें कपल का रोमांटिक अंदाज

एक्ट्रेस गौहर खान और जैद दरबार हनीमून के लिए उदयपुर पहुंच गए हैं। उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं। गौहर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हनीमून ट्रिप का एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में वह फिल्म दोस्ताना के गाने जानें क्यों पर डांस करती नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड में ओबेरॉय उदयविलास होटल का इंटीरियर दिख रहा है।

गौहर खान ने इस वीडियो को शेयर करते कैप्शन में लिखा, इस तरह मुझे खुशी मिलती है, जब मैं ट्रैवल करती हूं। और क्यों नहीं, यह हबी के साथ मेरी पहली ट्रिप है। जैद दरबार ने भी दो फोटो शेयर की हैं, जिसमें दोनों जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, आखिरकार हमारा समय सउदयपुर। तस्वीर में जैद और गौहर कैजुअल आउटफिट में पोज देते दिख रहे हैं। फोटो के बैकग्राउंड सन सेट हो रहा है।बता दें कि जैद और गौहर ने मुंबई में पिछले साल 25 दिसंबर को शादी की थी। इस दौरान उनके वेडिंग की तस्वीरें और वीडियोज जमकर वायरल हुए थे। शादी के बाद दोनों ने एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन दिया था, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे।

गौहर खान कई वेब सीरीज में काम करने से कर चुकी हैं इनकार

हाल ही में गौहर खान ने उन वेब शोज को लेकर बात की है, जिनके लिए उन्होंने इनकार किया, क्योंकि वह उनमें बोल्ड सीन्स नहीं करना चाहती थीं। पिछले एक या डेढ़ साल से गौहर खान किसी फिल्म और वेब सीरीज का हिस्सा नहीं रहीं, इस पर उनका कहना है कि वह खुद को उन रोल्स से कनेक्ट नहीं कर पाईं जो उन्हें ऑफर हुए। उन्होंने उनके लिए इनकार किया, क्योंकि उन्हें बोल्ड सीन्स करने में आपत्ति थी। गौहर कहती हैं कि मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे कोई बोल्ड सीन करना ही नहीं है। एक एक्टर के रूप में मेरा काम है दर्शकों तक अच्छी चीजें पहुंचाना और किरदार के साथ इंसाफ करना जो मैं किसी फिल्म या वेब सीरीज में निभा रही हूं। हां, मेरी कुछ शर्तें हैं, खासकर उस तरह के कॉन्टेंट के साथ, जिससे मैं जुड़ी हूं। मैं अपनी ये लाइन्स क्रॉस नहीं करूंगी, वह भी सिर्फ एक वेब शो या फिल्म का हिस्सा बनने के लिए।

गौहर आगे कहती हैं, एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे अपना काम दर्शकों तक बहुत ही समझदारी से पहुंचाना है, लेकिन मेरे लिए कुछ चीजें हैं, जैसे बोल्ड सीन और खुद को ग्लैमरस दिखाना, इसके लिए मैं सहज महसूस नहीं करती हूं। ऐसे में मैं काफी सोच-विचार के साथ प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं।

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा ने बिकिनी में ढाया कहर, गोवा वेकेशन से शेयर कीं PHOTOS

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर पत्नी मीरा राजपूत के साथ गोवा में वेकेशन मना रहे हैं। हाल ही में मीरा ने गोवा पहुंचने के बाद अपने रूम और पूल की फोटो शेयर की थी। अब उन्होंने अपनी एक बोल्ड तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह बिकिनी में नजर आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने गोवा से कई तस्वीरें फैन्स के साथ साझा की हैं जिन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है।

इस तस्वीर को मीरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है, जिसमें वह मिरर के सामने सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। फोटो में मीरा बिकिनी में काफी ग्लैमरस और बोल्ड लुक में दिख रही हैं। उन्होंने बिकिनी के ऊपर फ्लोरल प्रिंट श्रग पहन रखा है। मीरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी और भी तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में वह कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। उन्होंने ब्लैक नोटेड टॉप और पिंक ट्राउजर पहन रखा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आप मुझे जैस्मिन बुला सकते हैं शाहिद कपूर की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म जर्सी की रिलीज डेट का ऐलान किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें वह क्रिकेटर के लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में बताया कि उनकी फिल्म जर्सी दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को रिलीज होगी।

रिलीज के लिए उन्होंने दीपावली को ही क्यों चुना? इस बारे में बात करते हुए निर्माता अमन गिल ने कहा, दीपावली साल का सबसे बड़ा पारिवारिक त्योहार है, और दर्शकों के लिए एक पारिवारिक स्पोर्ट्स-ड्रामा जर्सी जैसी फिल्म लाने का यह सही समय है। यह ऐसा समय होता है जब पूरा परिवार एक साथ जश्न मनाता है।

फिल्म जर्सी में मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी हैं। यह गौतम तिन्ननुरी द्वारा निर्देशित है और इसमें संगीत टिपमर और परम्परा का है। फिल्म उसी नाम की व्यावसायिक रूप से सफल तेलुगू फिल्म की रीमेक है।

स्वदेश लौटने पर भारतीय टीम का जोरदार स्वागत

नई दिल्ली, एजेंसी। कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे आस्ट्रेलिया पर विजय हासिल करने के बाद गुरुवार को जब कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ स्वदेश पहुंचे तो वातावरण आला रे आला अजिंक्य आला के स्वरों से गूंज उठा। कप्तान रहाणे और कोच रवि शास्त्री सहित कुछ खिलाड़ी गुरुवार को स्वदेश पहुंचे और उनका यहां जोरदार स्वागत किया गया। रहाणे जब अपने आवासीय परिसर में पहुंचे तो पारंपरिक ढोल ताशा बज रहे थे और लोग आला रे आला अजिंक्य आला गा रहे थे। जब वह लाल कारपेट पर आगे बढ़ रहे थे तो लोग उन पर पुष्पवर्षा कर रहे थे। रहाणे के अलावा मुख्य कोच रवि शास्त्री, स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और सलामी बल्लेबाज पृथ्वी सॉव भी मुंबई पहुंचे जबकि ब्रिसबेन टेस्ट के नायक

ऋषभ पंत तड़के दिल्ली पहुंचे। पहले नेट गेंदबाज के रूप में चुने गये लेकिन बाद में एक दौरे के दौरान तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में पदार्पण करने वाले पहले क्रिकेटर बने तेज गेंदबाज टी नटराजन बेंगलुरू गये जहां से वह तमिलनाडु में अपने गांव सलेम जाएंगे। चेन्नई के रहने वाले अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, युवा आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और गेंदबाजी कोच भरत अरुण अभी दुबई में हैं और उनके शुक्रवार की सुबह स्वदेश पहुंचने की संभावना है। रहाणे, शास्त्री, रोहित, शार्दुल और सॉव का मुंबई पहुंचने पर मुंबई क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने स्वागत किया। रहाणे ने टीम की जीत का जश्न मनाने के लिये केक भी काटा।

रहाणे इसके बाद सीधे माटुंगा स्थित अपने आवासीय परिसर में पहुंचे तो वहां के निवासियों ने उनके शानदार स्वागत के लिये भरपूर तैयारियां कर रखी थी। रहाणे के वहां पहुंचने पर ढोल बजने लगे और पुष्पवर्षा होने लगी। रहाणे भी लोगों का यह प्यार देखकर आह्लादित थे। इनमें से कुछ तो कोविड-19 महामारी के बावजूद मास्क पहनकर हवाई अड्डे पर टीम का इंतजार कर रहे थे। यह बल्लेबाज जब अपने आवासीय परिसर में पहुंचा तो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। ढोल ताशा अमूमन किसी उपलब्धि का जश्न मनाने या खुशी के मौके पर बजाये जाते हैं। कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद भारत ने मंगलवार को ब्रिसबेन में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती और इस तरह से बोर्डर-गावस्कर ट्राफी अपने पास बरकरार रखी।

महाराष्ट्र सरकार ने रहाणे और अन्य खिलाड़ियों को दी क्वारंटीन में छूट

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर गुरुवार सुबह मुंबई लौटे कप्तान अजिंक्या रहाणे और चार अन्य भारतीय खिलाड़ियों को क्वारंटीन से छूट दी है। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और एमसीए की ओर से महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार की गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख और बीसीसीआई और एमसीए के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार से खिलाड़ियों को क्वारंटीन से छूट देने की अपील के बाद उन्हें राज्य में अनिवार्य 14 दिन के क्वारंटीन से छूट दी गई है।

फुटबॉल दिल्ली ने अंडर-16 खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की

नई दिल्ली,एजेंसी। फुटबॉल दिल्ली ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रतिभावान अंडर-16 खिलाड़ियों के अमेरिका और ब्रिटेन के कॉलेज में प्रवेश के लिए गुरुवार को स्कॉलरशिप की घोषणा की। क्रेयोन्स एकेडमी फोर स्किल्स एक्सीलेंस (सीएएसई) के सहयोग से यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रत्येक साल एक प्रतिभावान जूनियर लड़के और लड़की का चयन इस स्कॉलरशिप के लिए उनकी फुटबॉल और शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा। फुटबॉल दिल्ली और सीएएसई इन दो चयनित खिलाड़ियों का प्रवेश अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के कॉलेज में कराने के लिए काम करेगा। फुटबॉल दिल्ली के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरन ने कहा, कॉलेज खेलों को खेलना शिक्षा को

शीर्ष स्तर के प्रतिस्पर्धी खेलों से जोड़ने का शानदार तरीका है। यह शिक्षा से समझौता किए बगैर खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का मौका देता है। उन्होंने विज्ञप्ति में कहा, सीएएसई के साथ साझेदारी का लक्ष्य दिल्ली/एनसीआर के युवा फुटबॉलरों के समग्र विकास की दिल्ली फुटबॉल की प्रतिबद्धता है। पात्रता नियमों के अनुसार खिलाड़ी का सब जूनियर और जूनियर ओपन राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में अपने संबंधित राज्य का प्रतिनिधित्व करना जरूरी होगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की भी जरूरत पड़ेगी।

संक्षिप्त खबरें

रोनाल्डो के गोल से युवेंटस ने रिकार्ड नौवीं बार जीता सुपर कप

मिलान,एजेंसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल की मदद से युवेंटस ने नैपोली को 2-0 से हराकर रिकार्ड नौवीं बार इटालियन सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। रोनाल्डो ने 64वें मिनट में गोल करके युवेंटस को बढ़त दिलायी। नैपोली के पास मैच को अतिरिक्त समय तक खींचने का मौका था लेकिन उसके कप्तान लोरेंजो इनसाइन आखिरी क्षणों में मिली पेनल्टी पर गोल नहीं कर पाये। अल्वारो मोराता ने इंजुरी टाइम के पांचवें मिनट में युवेंटस की तरफ से दूसरा गोल करके उसकी खिताबी जीत सुनिश्चित की। युवेंटस ने नौंवी बार सुपर कप जीतकर अपने रिकार्ड को बेहतर किया है। उसके बाद एसी मिलान का नंबर आता है जिसने सात बार खिताब जीता है।

एडीलेड टूर्नामेंट से 11 महीने बाद टेनिस में वापसी करेगी एश बार्टी

एडीलेड, एजेंसी। विश्व की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी एश बार्टी एडीलेड में होने वाली एकदिवसीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता से 11 महीने बाद कोर्ट पर वापसी करेगी। बार्टी ने गुरुवार को कहा कि वह इस प्रदर्शनी मुकाबले में खेलेगी जिसमें सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका और सिमोना हालेप भी हिस्सा लेंगी। इस एकदिवसीय टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के भी चार शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और डोमिनिक थीम भी शामिल हैं। फ्रेंच ओपन 2019 की विजेता और पिछले साल आस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बार्टी ने फरवरी में कतर ओपन के बाद कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। बार्टी ने कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन में भाग नहीं लिया था। एडीलेड के बाद बार्टी की योजना मेलबर्न में डब्ल्यूटीए 500 टूर्नामेंट में खेलने की है। इसके बाद आठ फरवरी से आस्ट्रेलियाई ओपन शुरू हो जाएगा।

लैवोनडोवस्की के गोल से बायर्न ने लिपजिग पर चार अंक की बढ़त बनायी

बर्लिन,एजेंसी। रॉबर्ट लेवोनडोवस्की के पेनल्टी पर किये गये गोल से बायर्न म्यूनिख ने आग्सबर्ग को 1-0 से हराकर जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बायर्न ने पहले हाफ में दबदबा रखा लेकिन उसे इसका फायदा केवल 13वें मिनट में मिला जब लेवोनडोवस्की ने पेनल्टी को गोल में बदला। आग्सबर्ग ने दूसरे हाफ में अच्छा खेल दिखाया और कई मौके बनाये। वह हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाया। इस बीच उसने एक पेनल्टी भी गंवायी। लेवोनडोवस्की ने सत्र का अपना 22वां गोल किया जो 17 मैच के बाद लीग का नया रिकार्ड है। बायर्न के इस जीत से 39 अंक हो गये हैं। आरबी लिपजिग 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। लिपजिग ने एक अन्य मैच में एमिल फोर्सबर्ग के 70वें मिनट में किये गये गोल से यूनियन बर्लिन को 1-0 से हराया।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 50 प्रतिशत दर्शकों को अनुमति दे सकता है बीसीसीआई

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष अधिकारी इंग्लैंड के खिलाफ चेपॉक और मोटेरा स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैचों में स्टेडियम की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत दर्शकों को प्रवेश की अनुमति देने पर सोच रहे हैं। पहले दो टेस्ट चेन्नै में होंगे जबकि बाकी दो टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर खेले जाएंगे। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ मंगलवार को खत्म हुई सीरीज के दौरान दर्शकों को मैदान में प्रवेश की अनुमति दी थी। बोर्ड के एक सीनियर सूत्र ने कहा, ह्यफिलहाल हम टेस्ट मैचों के लिये 50 प्रतिशत दर्शकों को अनुमति दे सकते हैं। बीसीसीआई दोनों प्रदेश संघों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर रहा है। बीसीसीआई कोरोना मामलों पर भी नजर रखे हुए है और चेन्नै या अहमदाबाद में मामले बढ़ने पर फैसला बदला भी जा सकता है। सूत्र ने कहा, 'अगर जरूरी सावधानियों के साथ 50 प्रतिशत दर्शकों को अनुमति दी जाती है जो यह संकेत होगा कि आईपीएल के दौरान दर्शकों को प्रवेश दिया जा सकता है।' इस बीच इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड पहले दो टेस्ट के लिए टीम का चयन गुरुवार को करेगा। पहली बार खिलाड़ियों के कार्यभार को ध्यान में रखकर पूरी सीरीज के लिए टीम का ऐलान नहीं किया गया है।

भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने चिली की सीनियर टीम को हराया

सैंटियागो (चिली), एजेंसी। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके यहां प्रिंस ऑफ वेल्स कंट्री क्लब में चिली की सीनियर टीम को 3-2 से हराया। फर्नांडा विल्लाग्रान ने 21वें मिनट में चिली को बढ़त दिलायी जिसके बाद दीपिका (39वें मिनट), संगीता कुमारी (45वें मिनट) और लालरिंडिकी (47वें मिनट) ने भारत की तरफ से गोल दागे। चिली की सिमोन अवेली ने 56वें मिनट में गोल किया लेकिन इससे वह हार का अंतर ही कम कर पायी। भारत की इस दौरे में यह लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले उसने चिली की जूनियर टीम को दो मैचों में हराया था। भारत ने आक्रामक शुरूआत की और दो बार चिली के सर्किल में पहुंचा लेकिन गोल नहीं कर पाया। चिली को 10वें मिनट में पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन भारतीयों ने इसका अच्छा बचाव किया। चिली की टीम ने दूसरे क्वार्टर में दबदबा बनाया और इससे उसने 21वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कार्नर हासिल किये जिसमें से दूसरे पर विल्लाग्रान ने गोल किया। भारत ने तीसरे क्वार्टर में अच्छी वापसी की और नौ मिनट के अंदर पांच पेनल्टी कार्नर हासिल किये। इसका फायदा उठाकर दीपिका ने 39वें मिनट में टीम को बराबरी दिलायी। इसके बाद भारतीय टीम हावी हो गयी और 45वें मिनट में पेनल्टी कार्नर पर गोल करके बढ़त हासिल की। तब मारियाना कुजुर के ड्रैग फ्लिक को स्ट्राइकर संगीता ने डिफलेक्ट करके गोल में डाला था। भारत ने इसके बाद भी दबाव बनाये रखा और इसका लाभ उठाकर लालरिंडिकी ने संगीता के पास पर गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया।

डुप्लेसिस को उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने की

इस्लामाबाद, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को पिछले चार साल में पाकिस्तान का दो बार दौरा करने के बावजूद इस देश में इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट खेलने की उम्मीद नहीं थी। डुप्लेसिस ने गुरुवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिजीटल चैनल से कहा, यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे अपने करियर के दौरान उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि यहां सीमित ओवरों की क्रिकेट हो रही है लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट की वापसी होगी। डुप्लेसिस ने कहा, मैं इसके लिये तैयार हूं और उम्मीद है कि यह 13 साल पहले जैसी ही होगी। विकेट सपाट हैं और इसलिए हम बल्लेबाज कुछ रन बना सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका 13 साल में पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट श्रृंखला खेलेगा जिसमें यह 36 वर्षीय बल्लेबाज उसकी बल्लेबाजी का मुख्य आधार होगा। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में जबकि दूसरा टेस्ट चार फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। डुप्लेसिस ने 2017 में पाकिस्तान का दौरा किया था। तब उन्होंने टी20 श्रृंखला के लिये विश्व एकादश की अगुवाई की थी। वह पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान सुपर लीग प्लेऑफ खेलने के लिये भी पाकिस्तान आये थे। डुप्लेसिस ने कहा, वह (2017) पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिये पहला कदम था। पाकिस्तान के लिये यह महत्वपूर्ण है कि अब उसे घरेलू परिस्थितियों में खेलने का मौका मिलेगा।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया की 26 जनवरी की योजनाओं पर आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई

ब्रिसबेन, एजेंसी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अपनी स्वदेशी सलाहकार समिति की सिफारिश के बाद 26 जनवरी को तीन मैचों की मार्केटिंग में राष्ट्रीय अवकाश का उल्लेख करने से इनकार करने पर देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने नाराजगी जताई है। आस्ट्रेलिया दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1788 में कप्तान आर्थर फिलिप ब्रिटेन से 11 समुद्री जहाजों में सजा पाने वाले दोषियों को लेकर बोटेनी बे लाए थे जिसे अब सिडनी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आस्ट्रेलिया में जगह-जगह समारोह, परेड, महोत्सव के अलावा जश्न का आयोजन होता है लेकिन साथ ही विरोध-प्रदर्शन भी होते हैं। आस्ट्रेलिया के स्वदेश समुदाय के कई लोग इस दिन को आक्रमण के दिन के रूप में देखते हैं और इसके साथ ही

उपनिवेशवादियों के हाथों उनके उत्पीड़न और कष्टों की शुरूआत हुई और बाद में संघीय और राज्य सरकारों का रवैया भी ऐसा ही रहा। लंबे समय से राष्ट्रीय अवकाश को मनाने के लिए वैकल्पिक तिथि तलाशने को लेकर सार्वजनिक बहस चल रही है। आस्ट्रेलिया की बिग बैश टी20 लीग के 26 जनवरी को तीन मैच होने हैं और क्रिकेट आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय आदिवासी एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर क्रिकेट सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि इस दिन को आस्ट्रेलिया दिवस की जगह सिर्फ 26 जनवरी के रूप में पेश किया जाए। प्रधानमंत्री मौरिसन ने गुरुवार को मध्य क्वीन्सलैंड राज्य के रॉकथेम्पटन में एक रेडियो स्टेशन से कहा, क्रिकेट आस्ट्रेलिया को मेरा संदेश है कि वे क्रिकेट पर थोड़ा अधिक और राजनीति पर थोड़ा कम ध्यान दें। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह काफी साधारण सी चीज है। बिग बैश में 26 जनवरी को एक मुकाबला एडीलेड ओवल में और अन्य दो मुकाबले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने हैं।

तीसरे डिवीजन के क्लब से हारा रीयाल मैड्रिड

मैड्रिड, एजेंसी। रीयाल मैड्रिड तीसरे डिवीजन के क्लब अलकोयानो से हारकर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अलकोयानो की टीम आखिरी क्षणों में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी लेकिन इसके बावजूद उसने रीयाल मैड्रिड पर 2-1 से जीत दर्ज की। रीयाल ने एडिर मिलिताओ के 45वें मिनट में किये गये गोल से बढ़त बनायी लेकिन पूर्वी स्पेन के छोटे से क्लब अलकोयानो की तरफ से 80वें मिनट में जोस सोलबेस ने बराबरी का गोल दाग दिया। इससे मैच अतिरिक्त समय तक खिंच गया। अलकोयानो के लिये जुआन कासनोवा ने 115वें मिनट में विजयी गोल किया। इससे पांच मिनट पहले से उसकी टीम दस खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी।

आईओसी के पूर्व उपाध्यक्ष पाउंड : तोक्यो ओलंपिक के दौरान दर्शकों की मौजूदगी अनिवार्य नहीं

तोक्यो, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के पूर्व उपाध्यक्ष डिक पाउंड ने कहा है कि तोक्यो ओलंपिक का आयोजन स्टेडियम में दर्शकों की गैरमौजूदगी में हो सकता है। उन्होंने साथ ही भविष्यवाणी की कि जापान और दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद खेलों का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। पाउंड ने जापान की क्योदो समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, सवाल यह है- ऐसा (दर्शकों की मौजूदगी) अनिवार्य है या ऐसा होना अच्छा होता। दर्शकों का होना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। पाउंड अब फैसला करने वाले आईओसी के कार्यकारी बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं लेकिन वह स्थगित हो चुके तोक्यो ओलंपिक को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे। उन्होंने यह प्रतिक्रिया तब दी है जब हाल में जापान में एक सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाली 80 प्रतिशत जनता का मानना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ओलंपिक का आयोजन नहीं होना चाहिए। कनाडा के वरिष्ठ ओलंपिक अधिकारी और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के पहले अध्यक्ष पाउंड ने उस बात को दोहराया जिसे आईओसी और स्थानीय आयोजक महीनों से दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार खेलों का आयोजन नहीं हुआ तो इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। ये खेल दोबारा स्थगित नहीं होंगे।

समीर क्वार्टरफाइनल में, प्रणय बाहर

बैंकाक,एजेंसी। भारत के समीर वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क के रेस्मस गेमके को गुरूवार को लगातार गेमों में हराकर टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया जबकि एचएस प्रणय को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। समीर ने दूसरे दौर के मुकाबले में गेमके को 39 मिनट में 21-12, 21-9 से शिकस्त दी। समीर का क्वार्टरफाइनल में तीसरी सीड डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन से मुकाबला होगा। एंटनसन को भारत के किदाम्बी श्रीकांत से दूसरे दौर में वाकओवर मिल गया। प्रणय को मलेशिया के लियू डेरेन ने दूसरे दौर में 40 मिनट में 21-17, 21-18 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। मिश्रित युगल में सात्विकसैराज रेंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने जर्मन जोड़ी मार्क लेम्सफस और इसाबेल हर्टरिच को 56 मिनट 22-20, 14-21, 21-16 से हरा दिया।

ऋषभ पंत बोले, धोनी से तुलना शानदार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से तुलना से खुश हैं लेकिन उन्होंने गुरुवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभाने के बाद वह खेल में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। पंत की अक्सर दो बार के विश्व विजेता कप्तान धोनी से तुलना की जाती रही है। धोनी ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ब्रिसबेन के गाबा में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पंत ने नाबाद 89 रन बनाए और जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच विजेता पारी खेलने वाले पंत ने ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौटने के बाद पत्रकारों से कहा, जब आपकी तुलना धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी से की जाती है तो बहुत अच्छा लगता है और आप मेरी तुलना उनसे करते हैं। 23 साल के इस खिलाड़ी ने कहा, ह्ययह शानदार है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी से तुलना की जाए।

ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद सीधे पिता की कब्र पर पहुंचे सिराज

हैदराबाद, एजेंसी। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद सीधे अपने पिता की कब्र पर पहुंचे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती और बॉर्डर-गावसकर ट्रोफी पर भी कब्जा जमाया। सिराज का 63 दिनों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, जब यह युवा पेसर शमशाबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे खैरताबाद के कब्रिस्तान पहुंचे और अपने दिवंगत पिता मोहम्मद

गोस की कब्र पर फूल चढ़ाए। सिराज के 53 वर्षीय पिता का, जो एक ऑटो चालक थे, 20 नवंबर को फेफड़ों की बीमारी के कारण इंतकाल हो गया। सिराज तब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ थे और उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया।

भारत के पास प्रतिभा को निखारने की उचित व्यवस्था: हफीज

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने आस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की टेस्ट श्रृंखला में जीत की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभा को निखारने की उचित व्यवस्था के कारण ही यह संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को निखारने की अच्छी व्यवस्था नहीं है।

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की निगाहें जीत पर

गॉल,एजेंसी। इंग्लैंड को श्रीलंका में एक और टेस्ट श्रृंखला जीतने के लिये केवल एक ड्रा की जरूरत है लेकिन जो रूट की अगुआई वाली टीम शुक्रवार को शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में इसके बजाय नतीजा हासिल करने के बारे में सोच रही होगी। इंग्लैंड की टीम आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में भारत, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर है। चैम्पियनशिप का फाइनल जून में

खेला जायेगा और इसकी दौड़ में बने रहने के लिये इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत की जरूरत होगी और साथ ही भारत के दौरे पर उसे वहां श्रृंखला भी जीतनी होगी। इंग्लैंड ने 2007 के बाद से श्रीलंका में कोई श्रृंखला नहीं गंवायी है और स्पिन गेंदबाजी का बखूबी सामना कर सफलता हासिल की है। पहले टेस्ट में रूट का दबदबा रहा जिन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक जमाया और 228 रन की पारी खेली जिससे इंग्लैंड ने श्रीलंका को सात विकेट से हरा दिया।